सिर्फ इमारतें नहीं, इंसानों के सपने भी गढ़ रहा है ग्रेटर नोएडा | माटी से जुड़ाव, विरासत से संवाद | ललित मोहन रयाल: कलम की संवेदना, प्रशासन का संकल्प

RNI No.: UPHIN/2018/76675
वर्ष 7 । अंक 10 । अक्टूबर 2026 । ₹20

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका



स्थानीय हुनर से वैश्विक कारोबार तक



शोध से नीति तक, विकसित उत्तराखण्ड के नए युग की मजबूत नींव



सरकारी खरीद से ग्लोबल मार्केट तक– एमएसएमई के लिए नए अवसरों का द्वार



जब आइडिया कागज से निकलकर जमीन पर उतरेंगे

IFFCO KISAN DRONE

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

इफको नैनो उर्वरक अपनाएं
अधिक उपज और गुणवत्ता पाएं
इफको की असरदार जोड़ी

नैनो यूरिया प्लस

नैनो डीएपी

नैनो जिंक

नैनो कॉपर



अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री न. 1800-103-1967

www.iffco.in | www.nanourea.in I www.nanodap.in

इस अंक में





08
स्थानीय हुनर से वैश्विक कारोबार तक



14
शोध से नीति तक: विकसित उत्तराखण्ड के नए युग की मजबूत नींव



22
सफर आसान, कमाई मजबूत



26
नोएडा का नया विकास मॉडल



48
जब आइडिया कागज से निकलकर जमीन पर उतरेंगे

निर्माणशाला टाइम्स
हिंदी मासिक पत्रिका
मूल्यः 20 रुपये, अक्टूबर 2026
वर्ष-7 अंकः 10, पृष्ठः 52

प्रधान संपादक
मनोज कुमार सिंह
संपादक
अहमद हसन
सह संपादक
दिव्यांश मिश्रा

Website: www.nirmanshalatimes.com
E-mail: nirmanshalatimes@gmail.com
Mob: +919540284632

ब्यूरो प्रमुख

उत्तर प्रदेश-	**सी.बी. सिंह**
उत्तराखंड-	**विनय त्रिवाल**
दिल्ली-	**दिनेश कुमार सिंह**
बिहार-	**सैयद मोहम्मद अली**
हरियाणा-	**संतोष कुमार सिंह**
झारखंड-	**परवेज कमाल**
डिजाइन-	**चंद्रजीत कुमार**

विज्ञापन, प्रसार संपर्क और पत्र व्यवहार
NST MEDIA
WP-02, Block 'C'
Sector - 71, Noida - 201301
Distt. Gautam Buddha Nagar (UP)

कार्यालय
मुद्रक, प्रकाशक एवं स्वामी
सैयद नौशाद मंजर,
मुद्रित- नीलू प्रिंटिंग प्रेस, E-33,
सेक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश से,
प्रकाशित- टी-1,
श्री जी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-5,
नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से,
संपादक- अहमद हसन।
पत्र का नाम-
निर्माणशाला टाइम्स
(Nirmanshala Times)
RNI NO- UPHIN/2018/76675



संपादकीय

स्थानीय हुनर की वैश्विक उड़ान

UPITS 2026 : जब उत्तर प्रदेश की मिट्टी, हुनर और स्वाद ने दुनिया से संवाद किया

किसी प्रदेश की आर्थिक ताकत केवल बड़े उद्योगों और निवेश के आंकड़ों में नहीं दिखाई देती। उसकी असली शक्ति उन हाथों में होती है, जो पीढ़ियों से हुनर को संभाले हुए हैं; उन खेतों में होती है, जहां विशेष उपज तैयार होती है; और उन युवाओं में होती है, जो सीमित संसाधनों के बीच भी उद्यम का सपना देखते हैं। **उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2026** को इसी व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए।

25 सितंबर को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। 29 सितंबर तक चले इस आयोजन में **ऑस्ट्रिया, बेलारूस, जापान, रूस, सिंगापुर और वियतनाम** छह देशों की सहभागिता रही। अंतरराष्ट्रीय भागीदारी ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों और उद्यमों को वैश्विक कारोबारी संवाद का अवसर दिया।

लेकिन इस भव्य आयोजन की असली तस्वीर मंच की रोशनी से कहीं आगे दिखाई देती है। किसी जिले से आया वह कारीगर, जो अपने उत्पाद को बड़े कारोबारी के सामने रखते हुए उसके बारे में पूरे आत्मविश्वास से बताता है, दरअसल अपने साथ केवल एक वस्तु नहीं लाता—वह **अपनी पीढ़ियों की मेहनत और अपने जिले की पहचान** लेकर आता है। किसी छोटे शहर का युवा उद्यमी जब संभावित खरीदार को अपने मोबाइल पर उत्पाद की तस्वीर और उसकी बाजार संभावनाएं दिखाता है, तो उसमें बदलते भारत का नया आत्मविश्वास दिखाई देता है। किसी महिला उद्यमी के चेहरे की उम्मीद यह बताती है कि बाजार तक पहुंचने का एक अवसर किस तरह आत्मनिर्भरता की राह खोल सकता है।

यही वह मानवीय पक्ष है, जो **ODOP—वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट** को केवल सरकारी पहल से आगे ले जाता है। किसी जिले का विशिष्ट उत्पाद वहां की मिट्टी, परंपरा और श्रम की पहचान होता है। उसे बड़े बाजार तक पहुंचाना वास्तव में उस पहचान को सम्मान और आर्थिक अवसर देना है।

इसी तरह **ODOC—वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन** उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वाद को भी नई आर्थिक संभावना से जोड़ता है। किसी कस्बे की पुरानी रसोई में पीढ़ियों से बन रहा पारंपरिक व्यंजन जब बड़े मंच पर पहचान पाता है, तो उसके साथ स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, छोटे कारोबार और रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ती हैं। छह देशों की सहभागिता से यह संदेश भी मिलता है कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार का दायरा व्यापक हो रहा है। हालांकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए केवल अच्छा उत्पाद पर्याप्त नहीं होगा। **गुणवत्ता, डिजाइन, पैकेजिंग, तकनीक, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और निर्यात मानकों** पर निरंतर ध्यान देना होगा।

अब प्रदर्शनी से परिणाम की ओर

निर्माणशाला टाइम्स का संपादकीय दृष्टिकोण है कि UPITS की वास्तविक सफलता का आकलन आयोजन समाप्त होने के बाद होना चाहिए। कितने संपर्क व्यापार में बदले? कितने उत्पादों को नए बाजार मिले? कितने उद्यमियों को निर्यात के अवसर मिले? और क्या इसका असर उन छोटे हाथों तक पहुंचा, जिनकी मेहनत इन उत्पादों के पीछे है?

क्योंकि अंततः किसी ट्रेड शो की सबसे बड़ी उपलब्धि वह क्षण नहीं, जब कोई विदेशी खरीदार स्टॉल पर रुकता है; बल्कि वह दिन है, **जब उसी खरीदार का ऑर्डर किसी छोटे कस्बे की कार्यशाला में काम बढ़ाता है, किसी कारीगर के घर में आमदनी बढ़ाता है और किसी युवा को अपने गांव या शहर में ही भविष्य दिखाई देने लगता है।**

यही 'लोकल से ग्लोबल' का वास्तविक अर्थ है।

UPITS 2026 इसी संभावना का मंच है—जहां उत्तर प्रदेश अपने उत्पाद ही नहीं, अपनी मिट्टी, मेहनत, संस्कृति और उद्यमशीलता भी दुनिया के सामने रख रहा है।

हुनर स्थानीय हो सकता है, लेकिन यदि उसे सही बाजार और अवसर मिले, तो उसकी पहचान की कोई सीमा नहीं।



सिर्फ इमारतें नहीं, इंसानों के सपने भी गढ़ रहा है ग्रेटर नोएडा

श्रमिकों को सम्मानजनक आवास, युवाओं को ज्ञान का संसार और शहर को नई रफ्तार देने वाले ऐतिहासिक फैसले

किसी शहर की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों, चमचमाती सड़कों और बड़े उद्योगों से नहीं होती। एक सच्चे आधुनिक शहर की पहचान इस बात से होती है कि उसके विकास में समाज का अंतिम व्यक्ति कितना शामिल है। क्या उस शहर में श्रमिक के लिए सम्मानजनक आवास है? क्या युवा के सपनों को उड़ान देने के लिए अवसर हैं? क्या आम नागरिक सुरक्षित और सुगम जीवन जी सकता है?

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 144वीं बोर्ड बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय इन सवालों का सकारात्मक उत्तर देते दिखाई देते हैं। यह बैठक केवल प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक ऐसे ग्रेटर नोएडा की तस्वीर प्रस्तुत की है, जहां **विकास के केंद्र में केवल बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि इंसान और उसकी आकांक्षाएं भी हैं।**



श्रमिकों के सपनों को मिलेगा अपना घर

ग्रेटर नोएडा की औद्योगिक पहचान को मजबूत बनाने में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लाखों श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये श्रमिक शहर की इमारतें बनाते हैं, उद्योगों को गति देते हैं और विकास की बुनियाद तैयार करते हैं। लेकिन अक्सर यही श्रमिक सुरक्षित और सम्मानजनक आवास की चुनौती से जूझते हैं।

प्राधिकरण ने इस चुनौती को समझते हुए पतवाड़ी और बिरौंडी में ईडब्ल्यूएस आवास विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह पहल केवल मकान उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए **अपने घर का सपना साकार करने की दिशा में एक नई शुरुआत है।**

यह निर्णय अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या को कम करने के साथ-साथ श्रमिक परिवारों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधायुक्त जीवन देने में भी सहायक होगा।

रोजगार की तलाश में आएंगे, सम्मान के साथ ठहरेंगे

नए शहर में रोजगार की तलाश में आने वाले श्रमिकों के सामने सबसे पहली चुनौती अस्थायी

आवास की होती है। महंगे होटल और किराये के कमरे उनकी सीमित आय पर अतिरिक्त बोझ बनते हैं।

इसी आवश्यकता को देखते हुए इकोटेक क्षेत्र में ट्रांजिट लेबर हॉस्टल की दिशा में पहल की गई है। यहां श्रमिक कम किराये पर सुरक्षित आवास प्राप्त कर सकेंगे और रोजगार मिलने तक सम्मानजनक वातावरण में रह सकेंगे।

यह कदम एक संवेदनशील और दूरदर्शी शहरी विकास मॉडल का उदाहरण है, जहां शहर अपने निर्माणकर्ताओं को भी सुरक्षा और सुविधा देने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है।

जब किताबें बनेंगी युवाओं की ताकत

विकास की असली ताकत ज्ञान है। सेक्टर अल्फा-1 में प्रस्तावित सार्वजनिक पुस्तकालय इसी सोच को आगे बढ़ाता है।

यह पुस्तकालय बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी वर्गों के लिए ज्ञान का साझा मंच बनेगा। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह सुविधा किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगी।

जिन विद्यार्थियों के लिए महंगी किताबें खरीदना संभव नहीं है, उन्हें यहां न्यूनतम शुल्क पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

यह पुस्तकालय केवल पुस्तकों का भवन नहीं होगा, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों, संघर्षों और सफलताओं का भविष्य गढ़ने वाला ज्ञान केंद्र बन सकता है।

नई सड़कें, नई रफ्तार और नए अवसर

एक आधुनिक शहर की सफलता उसकी कनेक्टिविटी से भी तय होती है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से 130 मीटर रोड को जोड़ने के लिए प्रस्तावित डबल डेकर सड़क ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगी।

पहले चरण में 'एक मूर्ति' तक प्रस्तावित यह परियोजना आने वाले समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के बीच यात्रा को अधिक सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वहीं, 105 मीटर चौड़ी सड़क को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक और लॉजिस्टिक भविष्य को नई मजबूती देगी।

जब सड़कें तेज होती हैं, तो केवल वाहन नहीं दौड़ते—रोजगार, निवेश और अवसर भी नई रफ्तार पकड़ते हैं।

गांव की जरूरत भी विकास के एजेंडे में

शहरी विकास के साथ ग्रामीण सुविधाओं को प्राथमिकता देना समावेशी सोच का परिचायक है। ग्राम रिठौरी में रेलवे लाइन पर फुटओवर ब्रिज बनाने की मंजूरी स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

रैंप, सीढ़ियों और लिफ्ट की सुविधा के साथ







बनने वाला यह फुटओवर ब्रिज केवल आवागमन का साधन नहीं होगा, बल्कि सुरक्षित जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

आपदा के समय तुरंत पहुंचेगी मदद

एनडीआरएफ के क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र के लिए 30 फ्लैट निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय ग्रेटर नोएडा की आपदा प्रबंधन तैयारियों को और मजबूत करेगा।

भूकंप, भवन दुर्घटना, बाढ़, औद्योगिक हादसे या अन्य आपात स्थितियों में राहत और बचाव दल की त्वरित उपलब्धता अनमोल साबित होती है। यह पहल स्पष्ट करती है कि विकास केवल आज की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहने का नाम है।

स्वच्छ सड़कें, बेहतर हवा और स्वस्थ भविष्य

वायु प्रदूषण और धूल आज तेजी से विकसित हो रहे शहरों की बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

आधुनिक मशीनों के माध्यम से सड़कों की नियमित सफाई से धूल नियंत्रण और वायु



गुणवत्ता सुधार में मदद मिलेगी। यह निर्णय ग्रेटर नोएडा को केवल स्मार्ट ही नहीं, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने की सोच को भी मजबूत करता है।

भविष्य का शहर, इंसानों के लिए शहर

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 144वीं बोर्ड बैठक के निर्णयों में एक स्पष्ट संदेश छिपा है— **विकास का अर्थ केवल सीमेंट, कंक्रीट और निर्माण नहीं है।**

विकास का अर्थ है—

श्रमिक को घर, युवा को किताब, नागरिक को बेहतर सड़क, गांव को सुविधा, शहर को स्वच्छ हवा और आपदा के समय त्वरित सुरक्षा।

आज ग्रेटर नोएडा एक ऐसे नए विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां आधुनिक बुनियादी ढांचा और मानवीय संवेदनाएं एक साथ चल रही हैं।

यही वह सोच है, जो किसी शहर को केवल 'स्मार्ट सिटी' नहीं, बल्कि 'सेंसिटिव सिटी' बनाती है।

और शायद यही ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी पहचान बनने जा रही है—

"एक ऐसा शहर, जो केवल विकास नहीं करता... बल्कि विकास में हर व्यक्ति को साथ लेकर चलता है।" ■



UPITS 2026 ने पांच दिनों में दुनिया के सामने रखा उत्तर प्रदेश का औद्योगिक, कारोबारी और सांस्कृतिक सामर्थ्य

स्थानीय हुनर से वैश्विक कारोबार तक



25 सितंबर की सुबह इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में जब उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 का उद्घाटन हुआ, तो यह केवल एक प्रदर्शनी का शुभारंभ नहीं था। एक ही परिसर में प्रदेश के जिलों का हुनर, आधुनिक उद्योग, कृषि, तकनीक, हस्तशिल्प, स्टार्टअप, महिला उद्यमिता और भविष्य की औद्योगिक योजनाएं दुनिया के सामने थीं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री **अमित शाह** और मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** ने UPITS के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। पांच दिन तक चले इस आयोजन ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का व्यापक मंच दिया।



छह देशों की मौजूदगी, वैश्विक संवाद का विस्तार

इस बार **ऑस्ट्रिया, बेलारूस, जापान, रूस, सिंगापुर और वियतनाम** पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टनर देशों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल संवाद के माध्यम से व्यापार, निवेश और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। उद्घाटन दिवस पर ही पार्टनर देशों के प्रतिनिधियों के साथ पांच महत्वपूर्ण बैठकें हुईं।

ट्रेड शो में **Zen Alpha और Gen Z** की सहभागिता ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के गंभीर माहौल में नई पीढ़ी की रचनात्मक ऊर्जा भी जोड़ी। 28 से अधिक स्कूलों के 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने कला-संस्कृति प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। व्यापार और संस्कृति का यह मेल बताता रहा कि भविष्य का बाजार केवल उत्पादों से नहीं, प्रतिभा और रचनात्मकता से भी बनता है।



सरकार के विभागों के स्टॉल बने 'उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर'

UPITS में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने अपने-अपने स्टॉल के माध्यम से नीतियों, उपलब्धियों और निवेश अवसरों को सामने रखा। **नगर विकास, परिवहन, पुलिस, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रम, कृषि, कौशल विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, MSME और औद्योगिक विकास** से जुड़े विभागों की मौजूदगी ने आयोजन को केवल व्यापार प्रदर्शनी न रहकर शासन और अर्थव्यवस्था के साझा मंच का रूप दिया।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल,











केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद डॉ. महेश शर्मा, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', MSME मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रही।

ODOP से ODOC तक — जिलों की पहचान को बाजार

ODOP और ODOC UPITS के सबसे आकर्षक हिस्सों में रहे। प्रदेश के 75 जिलों के उत्पाद और खान-पान एक ही मंच पर दिखाई दिए। हस्तशिल्प से लेकर टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों तक स्थानीय पहचान को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रस्तुत किया गया। आधिकारिक विवरण के अनुसार ODOC में 75 जिलों के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंच का मंच मिला।

महिला उद्यमियों ने भी अपने उत्पादों के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके स्टॉलों पर स्थानीय उत्पादों के साथ आत्मनिर्भरता की कहानियां भी दिखाई दीं।

मेरठ की शिमला मिर्च से शहद तक कृषि कारोबार की चमक

मेरठ के स्टॉल पर पॉलीहाउस में तैयार रंगीन शिमला मिर्च, फूलों और शहद जैसे उत्पादों ने खरीदारों का ध्यान खींचा। यहां कृषि केवल खेत की उपज नहीं, बल्कि आधुनिक उत्पादन, पैकेजिंग और बाजार से जुड़ा व्यवसाय दिखाई दी।

इसी क्रम में संभल की **भारत हेम्प एग्रो** की कहानी विशेष रही। कंपनी ने लगभग 100 टन कृषि अवशेष को टेक्सटाइल फाइबर में बदला और अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया में निर्यात के लिए समझौते किए। यह उदाहरण कृषि अवशेष को कारोबार और निर्यात उत्पाद में बदलने की संभावनाओं को सामने लाता है।

YEIDA के स्टॉल पर 25 वर्षों की यात्रा और 2041 का सपना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहा। यहां प्राधिकरण की 25 वर्षों की विकास यात्रा के साथ **2041 के प्रथम चरण के मास्टर प्लान** का मॉडल प्रदर्शित किया गया।









नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, फिनटेक सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, जापान सिटी, कोरियन सिटी और अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं की झलक ने भविष्य के औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर सामने रखी।

नीति से कारोबार तक—पियूष गोयल का विशेष बिजनेस सेशन

तीसरे दिन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री **पीयूष गोयल** ने 'Leveraging India's Free Trade Agreements for Global Business Growth' विषय पर विशेष बिजनेस सेशन को संबोधित किया। FTA के माध्यम से भारतीय और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के उद्यमों के लिए वैश्विक बाजारों की संभावनाओं पर चर्चा हुई।



वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने श्रम संहिताओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़ते हुए कहा कि उद्योग और श्रमिक दोनों के हितों को साथ लेकर चलना जरूरी है।

समापन में आंकड़ों ने दिखाई पांच दिनों की तस्वीर

29 सितंबर को केंद्रीय वस्त्र मंत्री **गिरिराज सिंह** की मौजूदगी में UPITS 2026 का समापन हुआ। पांच दिनों में **4,400 MoU,** लगभग **6,500 करोड़ के समझौते, 15,500 करोड़ के संभावित कारोबार और 41,500 B2B बैठकें** इस आयोजन के कारोबारी परिणामों को रेखांकित करती हैं। करीब **5.99 लाख** आगंतुकों और बिजनेस खरीदारों की उपस्थिति भी दर्ज हुई।

UPITS 2026 की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर शायद यही रही कि यहां एक ओर बड़े उद्योग और वैश्विक खरीदार थे, तो दूसरी ओर छोटे कारीगर, महिला उद्यमी, किसान, युवा और स्थानीय उत्पाद। 25 सितंबर को शुरू हुई यह यात्रा 29 सितंबर को समाप्त जरूर हुई, लेकिन इसके स्टॉलों, समझौतों और मुलाकातों से बने कारोबारी संपर्क अब उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अगले बाजारों तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ■

किताबों से करियर तक, विरासत से जुड़ता युवा

UP International Trade Show में सूचना विभाग का पवेलियन बना ज्ञान, संस्कृति और डिजिटल अनुभव का आकर्षक पड़ाव







ग्रेटर नोएडा में आयोजित **उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो** में उद्योग और व्यापार की हलचल के बीच एक ऐसा पवेलियन भी था, जहां युवाओं की बातचीत निवेश या कारोबार से ज्यादा किताबों, प्रतियोगी परीक्षाओं और उत्तर प्रदेश की विरासत को लेकर सुनाई दी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का पवेलियन पांच दिनों तक युवाओं के लिए ज्ञान और अनुभव का एक अलग केंद्र बना रहा।

पुस्तकों की प्रदर्शनी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया। भारतीय इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान, उभरते भारत और उभरते उत्तर प्रदेश से जुड़ी पुस्तकों के साथ **उत्तर प्रदेश वार्षिकी** जैसी सामग्री युवाओं के लिए उपयोगी दिखाई दी। कई युवा पुस्तकों को पलटते, महत्वपूर्ण जानकारी देखते और पसंद आई पुस्तकों की जानकारी मोबाइल में दर्ज करते नजर आए।

सिकंदराबाद से आई पीसीएस अभ्यर्थी निधि यादव भी इसी तलाश में पवेलियन पहुंचीं। उन्हें अपनी क्लासमेट से उत्तर प्रदेश वार्षिकी के बारे में जानकारी मिली थी। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश से जुड़े प्रमाणिक तथ्यों और सामान्य ज्ञान की भूमिका को देखते हुए उनके लिए यह पुस्तक विशेष आकर्षण बनी।

सेल्फी के बहाने संस्कृति से मुलाकात

पवेलियन की दूसरी खासियत उसका सेल्फी जोन रहा। अयोध्या के राम मंदिर, वाराणसी का नमो घाट, वृंदावन का प्रेम मंदिर और सारनाथ जैसे स्थलों को पृष्ठभूमि में लेकर सेल्फी लेने के लिए युवाओं में खास उत्साह दिखाई दिया।

कई बार युवाओं को अपनी बारी के लिए करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन इंतजार में भी उत्साह कम नहीं हुआ। सेल्फी उनके लिए केवल तस्वीर लेने का माध्यम नहीं रही, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के साथ एक सहज डिजिटल जुड़ाव का अनुभव भी बनी।

इलेक्ट्रॉनिक ग्लोब ने इस अनुभव को और व्यापक बनाया। बच्चों और युवाओं को इसके माध्यम से उभरते भारत और उभरते उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखने का अवसर मिला। तकनीक और विरासत के इस मेल ने पवेलियन को ट्रेड शो के दूसरे व्यावसायिक स्टॉलों से अलग अनुभव दिया।

जब ज्ञान और अनुभव एक ही जगह मिले

पांच दिनों की यह गतिविधि एक महत्वपूर्ण बात सामने लाती है—आज का युवा केवल जानकारी पढ़ना नहीं चाहता, वह उसे **देखना, अनुभव करना और डिजिटल माध्यम से साझा करना** भी चाहता है। किताबों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और डिजिटल माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने का यह मेल इसी बदलती रुचि की झलक देता है।

व्यापार मेले में जहां उद्योग अपने उत्पाद और संभावनाएं प्रदर्शित कर रहे थे, वहीं सूचना विभाग का पवेलियन युवाओं को यह संदेश देता दिखाई दिया कि **विकास केवल आर्थिक आंकड़ों का नाम नहीं; ज्ञान, संस्कृति, तकनीक और नई पीढ़ी की भागीदारी भी उसकी अहम तस्वीर है।** ■





जब प्रदर्शनी बनी पहचान का मंच

UPITS-2026 में उत्कृष्ट पवेलियन और स्टॉल सम्मानित, सरकारी विभागों से लेकर उद्योग जगत तक की रचनात्मक प्रस्तुति को मिली पहचान

ग्रेटर नोएडा में आयोजित **उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026** का समापन केवल कारोबारी मुलाकातों और निवेश चर्चाओं के साथ नहीं हुआ। अंतिम दिन उन पवेलियन और स्टॉलों को भी सम्मान मिला, जिन्होंने अपने उत्पादों, तकनीक, योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। पुरस्कारों ने यह भी दिखाया कि किसी बड़े ट्रेड शो में प्रस्तुति अब केवल उत्पाद दिखाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि संस्थान की सोच और उसकी पहचान सामने रखने का माध्यम भी बन गई है।

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के विभिन्न हॉलों में प्रदेश सरकार के विभागों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, निजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों ने अपनी अलग-अलग कार्यशैली और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। **इन्वेस्ट यूपी, यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यूपीसीडा, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी** सहित अनेक प्रतिभागियों को सम्मान मिला।

सरकारी क्षेत्र की प्रस्तुति में **गृह (पुलिस), ओडीओपी-ओडीओसी, सूचना एवं**



जनसंपर्क, परिवहन, संस्कृति और आयुष विभाग के पवेलियन भी सम्मानित हुए। सूचना विभाग के पवेलियन में प्रदेश की विकास योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी पहलों को प्रदर्शित किया गया, वहीं संस्कृति और आयुष जैसे विभागों ने अपनी विशिष्ट पहचान को सामने रखा।

औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र की तस्वीर भी उतनी ही व्यापक रही। **यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, स्टार्टअप पवेलियन, एडवर्ब टेक्नोलॉजीज, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी** समेत अनेक संस्थानों को सम्मान मिला। पर्यटन, नगर विकास, कौशल विकास, बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र की भागीदारी ने प्रदर्शनी को बहुआयामी बनाया।

हॉल-11 और 12 में **उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान, वन निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कृषि उत्पादन मंडी परिषद** सहित विभिन्न प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। निजी क्षेत्र में भी अनेक कंपनियों और संस्थानों की प्रस्तुतियों को पुरस्कार मिला।

लेकिन इस आयोजन की एक और खास तस्वीर रही— **सम्मान केवल पवेलियन लगाने वालों तक सीमित नहीं रहा।** आयोजन को सफल बनाने में जुटी डीआईसी, पुलिस प्रशासन, ओडीओपी, ओडीओसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, सीएम युवा, आईईएमएल, ईपीसीएच और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी टीमों को भी सम्मान मिला।

इससे UPITS-2026 की एक व्यापक तस्वीर सामने आती है। एक तरफ उत्पाद, तकनीक और निवेश की संभावनाएं थीं, तो दूसरी तरफ उन्हें व्यवस्थित ढंग से लोगों और संभावित साझेदारों तक पहुंचाने वाली पूरी टीम। **पुरस्कारों का यह मंच वास्तव में उस सामूहिक प्रयास की पहचान बना, जिसने पांच दिनों तक उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और कारोबारी क्षमता को एक ही छत के नीचे प्रस्तुत किया।** ■



शोध से नीति तक

विकसित उत्तराखण्ड के नए युग की मजबूत नींव

हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर गांवों की अंतिम चौखट तक, उत्तराखण्ड आज विकास की एक नई सोच के साथ अपने भविष्य की इबारत लिख रहा है। राज्य स्थापना के 25 वर्षों की यात्रा के बाद देवभूमि अब केवल उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं कर रही, बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक ऐसी विकास रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें **शोध की गहराई, नवाचार की ऊर्जा, युवाओं की प्रतिभा और प्रभावी क्रियान्वयन की शक्ति** शामिल है।

उत्तराखण्ड के सामने भौगोलिक चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच असीम संभावनाओं का संसार भी मौजूद है। हिमालयी पर्यावरण, समृद्ध जैव विविधता, पर्यटन, कृषि, स्थानीय उत्पाद, युवा शक्ति और आधुनिक तकनीक—ये सभी मिलकर उत्तराखण्ड के भविष्य की नई तस्वीर गढ़ सकते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि विकास की नीतियां राज्य की वास्तविक परिस्थितियों, स्थानीय जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं।

'विकसित उत्तराखण्ड-2047' का सपना अब केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि शोध, नवाचार, सुशासन और जनभागीदारी के माध्यम से आकार लेती एक सशक्त विकास यात्रा है।

इसी दूरदर्शी सोच के साथ उत्तराखण्ड में नीति निर्माण को **शोध, डेटा, नवाचार और परिणाम आधारित क्रियान्वयन** से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखण्ड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस की शासी निकाय बैठक ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले वर्षों का उत्तराखण्ड केवल योजनाएं बनाने वाला राज्य नहीं, बल्कि शोध के आधार पर योजनाओं को गढ़ने, उनके परिणामों का मूल्यांकन करने और जरूरत के अनुसार उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने वाला राज्य होगा। ■





हुनर को मिला मंच, बेटियों को मिला रोजगार का अवसर

गौतमबुद्धनगर के पिंक रोजगार मेले में 486 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा, 263 युवतियां साक्षात्कार के बाद चयनित

शिक्षा और कौशल तभी सार्थक होते हैं, जब उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। गौतमबुद्धनगर में आयोजित पिंक रोजगार मेला इसी सोच को जमीन पर उतारने वाली पहल के रूप में सामने आया। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन विभाग द्वारा **राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, बादलपुर** में आयोजित इस मेले का केंद्र रहा— **शिक्षित छात्राओं एवं युवतियों को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से जोड़ना।**

मेले का शुभारंभ **दादरी विधायक तेजपाल नागर** ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर **जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर मेधा रूपम,** जिला सेवायोजन अधिकारी मनीषा अत्री, आर्या फैशन्स की संस्थापिका खुशबू सिंह तथा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, बादलपुर की प्रधानाचार्या दीपिका दुबे उपस्थित रहीं।

17 कंपनियां, 486 अभ्यर्थी और 263 चयन

रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों की **17 कंपनियों ने प्रतिभाग किया।** जिला सेवायोजन विभाग के अनुसार, **300 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन तथा 186 अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन पंजीकरण कराया। कुल 486 छात्राओं एवं युवतियों ने मेले में हिस्सा लिया।**

कंपनियों द्वारा आयोजित साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया के बाद 263 अभ्यर्थी चयनित किए गए। चयनित अभ्यर्थियों को कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति-पत्र भी वितरित किए गए।

यह उपलब्धि इस पहल की प्रत्यक्ष तस्वीर प्रस्तुत करती है कि रोजगारदाताओं और रोजगार की तलाश कर रही युवतियों को एक मंच पर लाने से चयन प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद मिल सकती है।



रोजगार के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा

पिंक रोजगार मेले का उद्देश्य केवल रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि युवतियों को उनकी **शैक्षणिक योग्यता, कौशल एवं प्रतिभा के अनुरूप निजी क्षेत्र के रोजगार अवसरों से जोड़ना था।**

इस तरह का मंच छात्राओं को कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद करने, उपलब्ध अवसरों को समझने और अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार विकल्प तलाशने का अवसर देता है।

'खुद को आम नहीं, खास बनाना है'

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी प्रतिभा और क्षमता पहचानने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवतियों के भीतर अपार शक्ति और क्षमता है और आवश्यकता इस बात की है कि वे अपनी प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग करें।

उन्होंने पिंक रोजगार मेले को बेटियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इस शुरुआत को आगे भी जारी रखा जाएगा, ताकि युवतियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

रोजगार संवर्धन के लिए एमओयू

कार्यक्रम के दौरान **जिला सेवायोजन कार्यालय, गौतमबुद्धनगर और युवा शक्ति फाउंडेशन के बीच रोजगार संवर्धन के लिए एमओयू** पर हस्ताक्षर भी किए गए। इससे रोजगार से जुड़े प्रयासों में संस्थागत सहयोग को आगे बढ़ाने का आधार तैयार हुआ।

बेटियों के सपनों को अवसर

पिंक रोजगार मेले की कहानी केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में वे **263 चयनित अभ्यर्थी** हैं, जिन्हें साक्षात्कार के बाद नियुक्ति-पत्र प्राप्त हुए।

गौतमबुद्धनगर में आयोजित यह पहल महिला सशक्तिकरण और युवतियों को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों की एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करती है। **सरकारी प्रयास, निजी क्षेत्र की भागीदारी और युवतियों की योग्यता—इन तीनों के बीच बना यह मंच रोजगार के नए अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया।** ■

माटी से जुड़ाव, विरासत से संवाद

माटी-पूर्वांचल महोत्सव में संस्कृति, प्रतिभा और गौरवशाली विरासत का सम्मान





माटी केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि वह भाव है जो व्यक्ति को अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान से जोड़ता है। इसी भाव को केंद्र में रखकर आयोजित **9वें माटी-पूर्वांचल महोत्सव** में बिहार के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पूर्वांचल की प्रतिभाओं का जीवंत संगम देखने को मिला। ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री **श्री सम्राट चौधरी** ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से बिहार के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने भावपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि **"माटी का फर्ज निभाना होगा, माटी का कर्ज लौटाना होगा।"** यह आह्वान अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की भावना को सामने रखता है।

साझी विरासत, साझा विकास की ताकत

मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल को बिहार और उत्तर प्रदेश की साझा सांस्कृतिक विरासत के रूप में रेखांकित किया। दोनों राज्यों की भाषा, लोक परंपराओं, खान-पान और सामाजिक संबंधों में दिखाई देने वाली समानताएं इस क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी और मानवीय संसाधन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बिहार की सांस्कृतिक विविधता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बज्जिका, मगही, मैथिली, भोजपुरी और अंगिका जैसी भाषाओं को राज्य की बहुरंगी पहचान का हिस्सा बताया। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि, भगवान महावीर की कर्मभूमि और भगवान बुद्ध से जुड़ी ज्ञान परंपरा का स्मरण करते हुए उन्होंने नालंदा की ऐतिहासिक शिक्षा व्यवस्था को बिहार की गौरवशाली विरासत का उदाहरण बताया।

विरासत से भविष्य की ओर

माटी महोत्सव का उद्देश्य केवल अतीत को याद करना नहीं, बल्कि उस विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में संस्था के प्रयासों की सराहना की। महोत्सव में लोकगीत-संगीत, पारंपरिक खान-पान, परिचर्चा और 'माटी सम्मान' जैसे आयोजन पूर्वांचल की सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर लाते हैं।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, मॉडल स्कूलों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के लिए 'बिहार विद्या साथी' ऐप जैसी पहलों की जानकारी दी।

प्रतिभाओं को मिला सम्मान

समारोह में कला, साहित्य, खेल, पत्रकारिता, बैंकिंग, न्याय, चिकित्सा, सामाजिक सेवा और खेल प्रशिक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इनमें पद्मश्री लोक गायिका **मालिनी अवस्थी,** पूर्व क्रिकेटर **सैयद सबा करीम,** वरिष्ठ पत्रकार **श्वेता सिंह,** बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी **ब्रजेश कुमार सिंह,** पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश **अरुण कुमार सिंह,** वरिष्ठ चिकित्सक **डॉ. राजीव रंजन,** देहात संस्था के संस्थापक-सीईओ **शशांक कुमार** तथा भारतीय फुटबॉल टीम की कोच एवं उपकप्तान **मधु कुमारी** शामिल रहीं। इन विभूतियों का सम्मान यह संदेश भी देता है कि किसी समाज की असली शक्ति उसकी प्रतिभाओं में होती है। उन्हें पहचान और मंच देना नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकता है।

माटी से मिलने की एक सार्थक पहल

'माटी' संस्था द्वारा आयोजित यह महोत्सव पूर्वांचल की सांस्कृतिक स्मृतियों और वर्तमान उपलब्धियों के बीच संवाद का मंच बनकर सामने आया। लोक परंपराओं से लेकर आधुनिक क्षेत्र की उपलब्धियों तक, आयोजन ने यह रेखांकित किया कि **अपनी जड़ों से जुड़कर ही भविष्य की मजबूत नींव तैयार की जा सकती है।**

यही इस महोत्सव का सबसे सकारात्मक संदेश है— **माटी को याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को समझते हुए भविष्य को संवारने का संकल्प भी है।** ■

25 हजार तक वेतन वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा का नया कवच

EPFO की बढ़ी वेतन सीमा से 51 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बचत, पेंशन और बीमा सुरक्षा का रास्ता होगा आसान



नौकरी से मिलने वाली हर महीने की आय परिवार की वर्तमान जरूरतें पूरी करती है, लेकिन एक कर्मचारी के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य EPFO कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है।** इस फैसले से **51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी** अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है।

इस निर्णय का सबसे बड़ा महत्व यह है कि अब 15,000 से अधिक और 25,000 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भी EPFO से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।

कर्मचारी को क्या मिलेगा लाभ?

पहला लाभ—भविष्य निधि की बचत। कर्मचारी के वेतन से निर्धारित योगदान PF खाते में जमा होता है और नियोक्ता भी इसमें योगदान करता है। इस तरह नौकरी के वर्षों में कर्मचारी के लिए एक दीर्घकालिक बचत तैयार होती रहती है, जिसका उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार भविष्य की जरूरतों में किया जा सकता है।

दूसरा लाभ—सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन। EPFO व्यवस्था से जुड़े पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन का आधार मिल सकता है। इससे नौकरी समाप्त होने के बाद आय के एक हिस्से की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलती है।

तीसरा लाभ—बीमा सुरक्षा। EPFO से जुड़ी कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बीमा लाभ मिल सकता है। यानी कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा के साथ उसके परिवार के लिए भी आर्थिक संरक्षण का एक आधार तैयार होता है।

चौथा लाभ—नियमित और संस्थागत बचत की आदत। PF में नियमित योगदान कर्मचारी को भविष्य के लिए व्यवस्थित बचत करने में मदद करता है। छोटी-छोटी मासिक बचत लंबे समय में एक बड़ी वित्तीय राशि का आधार बन सकती है।

रोजगार के साथ बचत, पेंशन और बीमा—ये तीनों मिलकर कर्मचारी के भविष्य का आर्थिक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। EPFO की नई वेतन सीमा इसी सुरक्षा को अधिक कर्मचारियों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आज की नौकरी, कल का सहारा

निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नौकरी के साथ सामाजिक सुरक्षा का जुड़ाव विशेष महत्व रखता है। बढ़ी हुई वेतन सीमा से ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, जिन्हें PF, पेंशन और बीमा जैसी व्यवस्थाओं का लाभ मिल सकता है।

इसका असर केवल कर्मचारी तक सीमित नहीं रहता। किसी कर्मचारी के भविष्य के लिए तैयार होने वाली PF बचत, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन और आकस्मिक परिस्थितियों में उपलब्ध बीमा सुरक्षा उसके परिवार के आर्थिक भविष्य को भी मजबूती देने में सहायक हो सकती है।

51 लाख से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचेगा सुरक्षा कवच

वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने से **51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के अनिवार्य EPFO कवरेज में आने की उम्मीद** है। इसका अर्थ है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा अब ऐसे कर्मचारियों तक भी विस्तृत होगा, जो पहले निर्धारित वेतन सीमा के कारण अनिवार्य कवरेज से बाहर थे। ■



रेशम के धागों में बुनी शम्भूनाथ की राष्ट्रीय पहचान

दुमका के किसान ने राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया झारखंड का गौरव, 'प्राइवेट ग्रेन्योर' श्रेणी में मिला सम्मान

किसी गांव की मिट्टी में पला-बढ़ा किसान जब अपने हुनर और मेहनत से राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित होता है, तो उसकी उपलब्धि केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं रह जाती। वह पूरे क्षेत्र और राज्य के लिए गौरव का विषय बन जाती है। **दुमका के मधुबन निवासी रेशम किसान श्री शम्भूनाथ देहरी** की कहानी भी ऐसी ही प्रेरक उपलब्धि की कहानी है, जिसने झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

बेंगलुरु के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में **केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस** के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में शम्भूनाथ देहरी को रेशम के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए **'प्राइवेट ग्रेन्योर' (निजी बीज उत्पादक)** श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री **श्री गिरिराज सिंह** ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।

दुमका से राष्ट्रीय मंच तक

झारखंड की पहचान लंबे समय से रेशम उत्पादन और इससे जुड़े ग्रामीण जीवन से भी जुड़ी रही है। ऐसे में दुमका के एक किसान का रेशम के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करना राज्य की इस परंपरा और संभावनाओं को नई पहचान देता है।

शम्भूनाथ देहरी ने रेशम के क्षेत्र में काम करते हुए निजी बीज उत्पादन की दिशा में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी इसी उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यह सम्मान उन किसानों के लिए भी उत्साह का संदेश है, जो पारंपरिक खेती के साथ कृषि से जुड़े नए अवसरों को अपनाकर अपनी आमदनी और पहचान दोनों बढ़ाना चाहते हैं।

मेहनत ने बदली पहचान

कृषि आज केवल परंपरागत खेती तक सीमित नहीं है। किसान बीज उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और रेशम उत्पादन जैसे क्षेत्रों से जुड़कर अपनी आय के नए रास्ते तलाश रहे हैं। शम्भूनाथ देहरी की उपलब्धि इसी बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करती है। 'प्राइवेट ग्रेन्योर' के रूप में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करना बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले किसान भी अपने अनुभव और विशेषज्ञता के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं। उनकी सफलता दुमका के ग्रामीण अंचल से निकलकर देश के बड़े मंच तक पहुंची है।

झारखंड के लिए गौरव का क्षण

बेंगलुरु में आयोजित इस समारोह में झारखंड के हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशक सहित विभिन्न राज्यों के निदेशक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस राष्ट्रीय समारोह में झारखंड के किसान को सम्मान मिलना राज्य के लिए गौरवपूर्ण क्षण रहा।

शम्भूनाथ देहरी का सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि **गांव की प्रतिभा, किसान की मेहनत और स्थानीय हुनर की राष्ट्रीय पहचान** का प्रतीक है। रेशम के महीन धागों से जुड़ा उनका यह सफर यह भरोसा जगाता है कि गांवों में मौजूद हुनर को अवसर मिले तो वह न केवल परिवार की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है, बल्कि पूरे राज्य का नाम भी राष्ट्रीय पटल पर रोशन कर सकता है। ■



गांवों में लौटती रौनक, होम स्टे से साकार होता आत्मनिर्भर पहाड़

पर्यटन ने खोले रोजगार के द्वार, युवाओं और महिलाओं को मिला स्वरोजगार का नया अवसर

उत्तराखण्ड के पहाड़ों में पर्यटन अब केवल घूमने-फिरने का माध्यम नहीं, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का जरिया बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की **होम स्टे नीति** ने ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा दी है। इसका असर गांवों में दिखाई दे रहा है, जहां युवा और महिलाएं होम स्टे व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं।

राज्य में अब तक **पांच हजार से अधिक होम स्टे संचालित** हो रहे हैं। वहीं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में ***537 लाभार्थियों को 79 करोड़ 28 लाख 18 हजार रुपये की अनुदान राशि*** दी जा चुकी है। पर्वतीय क्षेत्रों में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत, अधिकतम 15 लाख रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत, अधिकतम 7.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है।

रिवर्स पलायन को मिला नया आधार

होम स्टे योजना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में ग्रामीण क्षेत्रों में लौटते लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होना भी शामिल है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब **6,500 प्रवासी अपने गांव लौटे हैं,** जिनमें 22 प्रतिशत से अधिक ने होम स्टे व्यवसाय को अपनाया है। इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार के बीच एक मजबूत कड़ी बनती दिखाई दे रही है।

सारी गांव बना ग्रामीण पर्यटन की मिसाल

रुद्रप्रयाग का **सारी गांव** इस बदलाव की प्रभावी तस्वीर प्रस्तुत करता है। गांव में 40 से अधिक होम स्टे संचालित हैं और बड़ी संख्या में ट्रेकर्स एवं पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की आवाजाही ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ-साथ भोजन, परिवहन, स्थानीय उत्पादों और अन्य सेवाओं के लिए भी अवसर बढ़ाए हैं।

जादुंग में पर्यटन की नई दस्तक

उत्तरकाशी का सीमांत जादुंग गांव भी अब पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। सरकार ने इसे होम स्टे क्लस्टर के रूप में विकसित करने की पहल की है। यहां छह होम स्टे का निर्माण अंतिम चरण में है। कभी सामरिक परिस्थितियों के कारण खाली हुए इस सीमांत गांव में पर्यटन की गतिविधियों का विस्तार ग्रामीण जीवन में नई संभावनाओं का संकेत है। इसके अलावा **ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान** योजना के तहत बीते चार वर्षों में 258 पात्र लोगों को लाभ मिला है। इसका उद्देश्य पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। होम स्टे नीति की खासियत यह है कि इसमें स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक खान-पान और पहाड़ी जीवनशैली को पर्यटकों से जोड़ने का अवसर मिलता है। यही वजह है कि उत्तराखण्ड में होम स्टे अब **रोजगार, पर्यटन और गांवों की खुशहाली को जोड़ने वाली पहल** के रूप में उभर रहा है। **मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश है— "हमारे गांव खुशहाल होंगे तो प्रदेश और देश भी खुशहाल होंगे।"** उत्तराखण्ड के गांवों में बढ़ती पर्यटकीय गतिविधियां इस सोच को जमीन पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दिखाई देती हैं। ■



धान के साथ तालाब में तैरने लगे सपने

महासमुंद के किसानों ने मछली पालन से खोजी आमदनी की नई राह, दिनेश और हिमांशु की मेहनत बनी बदलाव की मिसाल

किसान की जिंदगी मौसम, मेहनत और उम्मीद के बीच आगे बढ़ती है। कभी फसल अच्छी होती है तो चेहरे पर मुस्कान आती है, और कभी बढ़ती लागत चिंता बढ़ा देती है। ऐसे में महासमुंद के किसानों ने अपनी मेहनत को एक नए रास्ते से जोड़ने का फैसला किया। **धान की खेती के साथ मछली पालन** ने उनके खेतों और परिवारों में आय का एक अतिरिक्त सहारा तैयार किया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से महासमुंद जिले के करीब **150 किसान** मत्स्य पालन से जुड़े हैं। किसी ने तालाब बनाया, किसी ने हैचरी स्थापित की और किसी ने पाउंड लाइनर यूनिट के जरिए इसे व्यवसाय का रूप दिया।

दिनेश ने तालाब में बोया एक नया सपना

बिरकोनी के किसान **दिनेश चन्द्राकर** के सामने पारंपरिक खेती में बढ़ती लागत एक चुनौती थी। उन्होंने इसी चुनौती के बीच एक नया रास्ता चुना—मछली पालन।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत करीब **7.50 लाख रुपये की लागत से एक हेक्टेयर में तालाब** तैयार कराया। इसके बाद लगभग **14 लाख रुपये की लागत से 20 हजार वर्गफुट में मछली हैचरी** स्थापित की। आज उनके लिए यह तालाब केवल पानी का एक क्षेत्र नहीं, बल्कि मेहनत और उम्मीद का नया आधार है। हैचरी में तैयार मछली के बच्चों को तालाब में डाला जाता है और करीब **8 से 9 महीने में 15 टन तक मछली** तैयार हो जाती है।

दिनेश के अनुसार, एक किलो मछली तैयार करने में करीब **70 से 80 रुपये** की लागत आती है, जबकि बाजार में यह लगभग **120 से 150 रुपये प्रति किलो** तक बिकती है। खेती के साथ यह गतिविधि उनके लिए अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनी है।

हिमांशु ने मेहनत को बनाया व्यवसाय

बकमा के **हिमांशु चंद्राकर** ने भी मछली पालन में अपनी संभावनाएं तलाशीं। करीब **28 लाख रुपये की लागत से दो पाउंड लाइनर यूनिट** तैयार कर उन्होंने इसे व्यवसाय का रूप दिया। उन्हें योजना के तहत **60 प्रतिशत अनुदान** मिला। हिमांशु बताते हैं कि सभी खर्च निकालने के बाद उन्हें सालाना करीब **3 से 4 लाख रुपये की बचत** हो जाती है। उनके लिए मछली पालन अब परिवार की आय का एक मजबूत जरिया बन गया है।



इन तालाबों से सिर्फ मछली नहीं, रोजगार भी निकल रहा है

इस बदलाव की कहानी किसानों तक ही सीमित नहीं है। मछली पालन से जुड़े काम ने गांव के श्रमिकों के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए हैं। बिरकोनी के कुछ मजदूरों के लिए अब गांव में ही काम उपलब्ध हो रहा है। करीब **9 हजार रुपये प्रतिमाह की आय** से उन्हें परिवार का खर्च चलाने में मदद मिल रही है।

यानी जिस तालाब में मछलियां पाली जा रही हैं, वहीं से किसी किसान के परिवार की अतिरिक्त आय और किसी श्रमिक के घर का चूल्हा भी चल रहा है।

मेहनत ने बदली खेती की तस्वीर

महासमुंद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से तालाब, हैचरी, पाउंड लाइनर, बायोफ्लॉक यूनिट सहित मत्स्य गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। किसानों के लिए यह खेती के साथ आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने का अवसर बन रहा है।

दिनेश के तालाब से लेकर हिमांशु की पाउंड लाइनर यूनिट तक, यह कहानी सिर्फ मछली पालन की नहीं है। यह उस किसान की कहानी है जो परिस्थितियों के सामने रुकने के बजाय नया रास्ता तलाशता है।

धान की फसल के साथ अब तालाब में पल रही मछलियों में भी उनकी उम्मीदें तैर रही हैं— **बेहतर आमदनी की, अपने गांव में रोजगार की और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य की।** ■

मिट्टी से मिली नई पहचान, तकनीक से बढ़ी उम्मीद

सरकारी सहयोग से अंतरा ने पॉली हाउस में रची आधुनिक खेती की नई कहानी



खेती सिर्फ फसल उगाने का माध्यम नहीं, बल्कि किसान के सपनों और आत्मनिर्भरता का आधार भी है। बदलते समय के साथ जब कृषि में तकनीक का समावेश हो रहा है, तब किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर संरक्षित खेती जैसे आधुनिक विकल्पों को अपना रहे हैं। गौतमबुद्धनगर के ग्राम सरकपुर की महिला कृषक **श्रीमती अंतरा कुमारी** इसी बदलती कृषि सोच की प्रेरक मिसाल हैं।

अंतरा ने सरकारी योजना के सहयोग से **2,500 वर्गमीटर क्षेत्र में पॉली हाउस स्थापित कर विभिन्न सब्जियों की संरक्षित खेती शुरू की है। उनका यह कदम केवल खेती** की तकनीक में बदलाव नहीं, बल्कि अपने खेत को नई संभावनाओं से जोड़ने की एक सकारात्मक पहल है।

पारंपरिक खेती से आधुनिक तकनीक की ओर कदम

खेती में नई तकनीक अपनाना किसी भी किसान के लिए सीखने, समझने और जोखिम उठाने की प्रक्रिया होती है। अंतरा कुमारी ने इसी चुनौती को अवसर में बदलने का निर्णय लिया। पॉली हाउस के माध्यम से उन्होंने मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण में सब्जियों की खेती का विकल्प चुना।

संरक्षित खेती ने उन्हें खेती को अधिक व्यवस्थित तरीके से करने का अवसर दिया। पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती के साथ वह आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनी जमीन पर उतार रही हैं।

सरकारी सहयोग ने दिया नई शुरुआत को आधार

आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने में प्रारंभिक निवेश महत्वपूर्ण होता है। अंतरा कुमारी को उद्यान विभाग के माध्यम से मिलने वाले सरकारी सहयोग ने इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया।

उनकी पॉली हाउस परियोजना की **कुल लागत 40 लाख** है। इसमें **20 लाख कृषक अंश तथा 20 लाख अनुदान** शामिल है। अर्थात परियोजना लागत का **50 प्रतिशत सहयोग अनुदान के रूप में मिला,** जबकि शेष 50 प्रतिशत कृषक अंश है।

यह आर्थिक सहयोग उनके लिए आधुनिक संरक्षित खेती की शुरुआत का महत्वपूर्ण आधार बना। योजना से मिले सहयोग को उन्होंने अपनी मेहनत और नई सोच के साथ जोड़कर खेती को नई दिशा देने का प्रयास किया।

महिला किसान के आत्मविश्वास की कहानी

अंतरा की पहल इस बात को भी रेखांकित करती है कि ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र में केवल भागीदारी ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक को अपनाकर नेतृत्वकारी भूमिका भी निभा सकती हैं।

2,500 वर्गमीटर में स्थापित पॉली हाउस आज उनके खेत की नई पहचान बन चुका है। यहां सब्जियों की खेती के साथ तकनीक, मेहनत और आत्मविश्वास का मेल दिखाई देता है।

उनकी पहल आसपास की अन्य महिला किसानों के लिए भी यह संदेश देती है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर और उपलब्ध अवसरों का उपयोग करके कृषि में नए विकल्प तलाशे जा सकते हैं।

एक पॉली हाउस, अनेक संभावनाएं

सरकपुर की अंतरा कुमारी की कहानी यह बताती है कि खेती में बदलाव की शुरुआत एक छोटे लेकिन दृढ़ निर्णय से हो सकती है। सरकारी सहयोग ने उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने में मदद की, जबकि उनकी मेहनत ने उस सहयोग को खेत में वास्तविक रूप दिया। आज उनके पॉली हाउस में उगती सब्जियां केवल कृषि उत्पादन की तस्वीर नहीं हैं, बल्कि **आधुनिक सोच, महिला आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की संभावनाओं** का भी प्रतीक हैं।

नई तकनीक के साथ नई उम्मीद

अंतरा कुमारी की सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जब **सरकारी योजना, आधुनिक तकनीक और किसान की मेहनत** एक साथ आती है, तो खेती में नए रास्ते खुलते हैं। सरकपुर के खेत में खड़ा यह पॉली हाउस आने वाले कल की उस कृषि तस्वीर की झलक देता है, जहां परंपरा के साथ तकनीक कदमताल कर रही है और किसान अपनी जमीन से नई संभावनाएं तलाश रहा है। ■

अंतरा की कहानी सिर्फ सब्जियां उगाने की कहानी नहीं, बल्कि उस नई उम्मीद की कहानी है जो तकनीक के सहारे खेतों में आकार ले रही है।

सफर आसान, कमाई मजबूत

75 जिलों में 'भारत टैक्सी' से बदल सकती है परिवहन की तस्वीर

जीरो कमीशन, नो-सर्ज प्राइसिंग और सहकारी मॉडल से यात्रियों के साथ सारथियों को भी मिलेगा लाभ



जब किसी गांव के व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल जाना हो, किसी विद्यार्थी को रेलवे स्टेशन पहुंचना हो या किसी परिवार को जरूरी काम से शहर की यात्रा करनी हो, तब स्थानीय परिवहन की उपलब्धता सीधे उसकी सुविधा और समय से जुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में **'भारत टैक्सी' मॉडल को सभी 75 जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार देने की तैयारी** इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है।

लखनऊ-कानपुर में सक्रिय इस मॉडल को प्रदेशव्यापी स्वरूप देने की योजना है। इसके तहत **बाइक, ऑटो और कैब** जैसी सेवाओं को शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि योजना को केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि टैक्सी चालकों को भी सहकारी व्यवस्था में भागीदार बनाने की परिकल्पना की गई है।

यात्रियों को क्या मिलेगा?

'भारत टैक्सी' के विस्तार से सबसे पहला लाभ परिवहन के विकल्प बढ़ने के रूप में सामने आएगा। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल, बाजार या जिला मुख्यालय तक जाने के लिए स्थानीय स्तर पर संगठित टैक्सी सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

नो-सर्ज प्राइसिंग का प्रावधान यात्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। मांग बढ़ने के समय किराये में अचानक होने वाली वृद्धि से अलग यह मॉडल यात्रियों को अधिक पूर्वानुमेय किराये का विकल्प देने की दिशा में है। इससे जरूरी यात्रा के दौरान बजट का अनुमान लगाना आसान हो सकता है।

चालकों की कमाई में कमीशन का दबाव नहीं

योजना का दूसरा बड़ा लाभ टैक्सी चलाने वाले **सारथियों** से जुड़ा है। प्रस्तावित **जीरो कमीशन मॉडल** में प्रति यात्रा प्लेटफॉर्म कमीशन काटने के बजाय सहकारी व्यवस्था के माध्यम से चालक को कारोबार में हिस्सेदारी देने की अवधारणा है।

अर्थात चालक केवल वाहन चलाकर सेवा देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवहन व्यवस्था से जुड़े कारोबारी ढांचे का भागीदार बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे उसकी आय और कारोबार में भागीदारी को मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।







गांवों में परिवहन के साथ स्वरोजगार

योजना का ग्रामीण विस्तार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। **PACS यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों** के माध्यम से 'भारत टैक्सी' को गांवों तक पहुंचाने की तैयारी है।

इससे दोहरा लाभ संभव है—एक ओर ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय परिवहन मिलेगा, दूसरी ओर गांव के युवाओं और वाहन संचालकों के लिए **स्वरोजगार का नया अवसर** विकसित हो सकता है। किसी ग्रामीण परिवार को अस्पताल या बाजार जाने के लिए निजी वाहन पर निर्भरता कम हो, स्थानीय चालक को नियमित काम मिले और गांव से जिला मुख्यालय तक आवागमन आसान हो—तो इसका असर केवल यात्रा तक सीमित नहीं रहता। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों तक पहुंच भी बेहतर हो सकती है।



75 जिलों तक पहुंच का बड़ा अर्थ

राजधानी और बड़े शहरों तक सीमित परिवहन सुविधा को जिलों और गांवों तक ले जाने से प्रदेश में स्थानीय कनेक्टिविटी का नेटवर्क व्यापक करने का अवसर मिलेगा। खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में जहां टैक्सी विकल्प सीमित हैं, वहां यह एक अतिरिक्त संगठित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करा सकता है।

योजना के चार प्रमुख लाभ

यात्री के लिए — परिवहन का नया विकल्प और नो-सर्ज प्राइसिंग।

चालक के लिए— जीरो कमीशन और सहकारी कारोबार में हिस्सेदारी की संभावना।

गांव के लिए— स्थानीय परिवहन सुविधा और स्वरोजगार के अवसर।

प्रदेश के लिए— बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन सेवाओं का व्यापक नेटवर्क।

सिर्फ टैक्सी नहीं, अवसरों का नेटवर्क

'भारत टैक्सी' का प्रस्तावित विस्तार परिवहन सुविधा को सहकारिता और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास है। यदि यह मॉडल योजनानुसार प्रदेश के 75 जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचता है, तो इसका प्रभाव यात्रा की सुविधा से आगे जाकर स्थानीय आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच सकता है। ■

शहर से गांव तक आसान सफर, यात्रियों के लिए पारदर्शी विकल्प और सारथियों के लिए कारोबार में भागीदारी—'भारत टैक्सी' उत्तर प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में सुविधा और स्वरोजगार को एक साथ आगे बढ़ाने वाली पहल के रूप में आकार ले रही है।

विशेष

ऋषिकुल में आकार लेगा भारतीय ज्ञान का नया अध्याय

आयुर्वेद, योग, मेडिकल टूरिज्म और प्राच्य विद्याओं के समन्वय से विकसित होगा विशिष्ट केंद्र



हरिद्वार की पहचान केवल मां गंगा के पावन तट और आध्यात्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। यह वह भूमि है, जहां भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं ने सदियों से मानव जीवन को दिशा दी है। अब इसी विरासत को आधुनिक आवश्यकताओं से जोड़ते हुए ऋषिकुल को एक ऐसे विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है, जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ दिखाई देंगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हरिद्वार स्थित **श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान, ऋषिकुल** के समग्र विकास से संबंधित प्रस्तावित मास्टर प्लान की समीक्षा करते हुए इसे आयुर्वेद, योग और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऋषिकुल की विकास अवधारणा में **आयुर्वेद, मेडिकल टूरिज्म, योग, ज्योतिष और वैदिक गणित** जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रमुखता दी जाए।

यह पहल केवल परिसर के भौतिक विकास तक सीमित नहीं होगी। यहां उच्च स्तरीय **शैक्षणिक, शोध एवं अध्ययन** की व्यवस्थाएं विकसित करने की परिकल्पना है, ताकि ऋषिकुल भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शोध के बीच एक प्रभावी सेतु बन सके।

ऋषिकुल का यह नया स्वरूप केवल एक संस्थान का कायाकल्प नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड की प्राचीन ज्ञान-संपदा को आधुनिक विश्व से जोड़ने का प्रयास होगा। यदि परंपरा की जड़ों को आधुनिक शोध और तकनीक के पंख मिलें, तो ऋषिकुल आने वाले समय में भारतीय ज्ञान, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म के एक ऐसे केंद्र के रूप में उभर सकता है, जिसकी पहचान उत्तराखंड से निकलकर देश और दुनिया तक पहुंचे।



विरासत की झलक, आधुनिक सुविधाओं का साथ

ऋषिकुल के प्रस्तावित स्वरूप की सबसे खास बात इसका प्राच्य एवं **पारंपरिक स्थापत्य और आधुनिक सुविधाओं** का संतुलित समन्वय होगा। भवनों के बाहरी स्वरूप और फसाड में प्राचीन स्थापत्य परंपरा की झलक होगी, वहीं परिसर में उपलब्ध सुविधाएं आधुनिकतम मानकों के अनुरूप विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परिसर की मूल अवधारणा उसके प्रत्येक हिस्से में स्पष्ट दिखाई दे। यहां आने वाला व्यक्ति केवल भवनों को न देखे, बल्कि उसे **भारतीय संस्कृति, ज्ञान, अध्यात्म और जीवन-दर्शन की अनुभूति** भी हो।

हरिद्वार की वैश्विक पहचान से जुड़ेगा ऋषिकुल

मां गंगा के कारण हरिद्वार देश-दुनिया के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में ऋषिकुल के विकास की अवधारणा को हरिद्वार की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भविष्य में यहां आने वाले लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म की समृद्ध विरासत को **जानने, समझने और अनुभव करने** का अवसर मिल सकेगा। प्रस्तावित मास्टर प्लान में योग एवं ध्यान, आयुर्वेद एवं समग्र स्वास्थ्य, भारतीय दर्शन, वैदिक एवं शास्त्रीय अध्ययन, कला-संस्कृति तथा शोध गतिविधियों को एकीकृत स्वरूप देने की परिकल्पना की गई है। मुख्यमंत्री ने परियोजना के सभी कार्यों को **चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से दो वर्ष के भीतर पूरा करने** तथा नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ■



सिमडेगा ने रचा प्रशासनिक नवाचार का नया अध्याय

जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को AI प्रशिक्षण देने वाला राज्य का अग्रणी जिला बना सिमडेगा

सरकारी प्रशासन की कार्यशैली में तकनीक को शामिल करना अब समय की आवश्यकता बन चुका है। इसी बदलते दौर में **सिमडेगा जिला प्रशासन ने एक उल्लेखनीय प्रशासनिक पहल करते हुए जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए दो दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कार्यशाला आयोजित कर एक नई मिसाल पेश की है।** इस पहल के साथ सिमडेगा जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को AI प्रशिक्षण प्रदान करने वाले राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि AI को प्रशासनिक कार्यों से जोड़ने का उद्देश्य केवल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था को **तेज, गुणवत्तापूर्ण, दक्ष, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित** बनाना है। सिमडेगा जिला प्रशासन ने क्षमता निर्माण को इस तकनीकी बदलाव की पहली सीढ़ी बनाया है।

प्रशासनिक क्षमता निर्माण की अभिनव पहल

10 और 11 सितंबर को आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य पदाधिकारियों और कर्मियों को AI की अवधारणा, इसके उपयोग और सरकारी कार्यों में इसकी संभावनाओं से परिचित कराना रहा। कार्यशाला को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार का तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ।

उपायुक्त **श्रीमती कंचन सिंह** ने कहा कि नई तकनीकों और AI के प्रभावी उपयोग से प्रशासनिक कार्यों में गति और गुणवत्ता लाई जा सकती है। उनके अनुसार इससे पदाधिकारी कम समय में अधिक प्रभावी तरीके से कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे तथा नागरिकों तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी।

कुशल प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम

सिमडेगा जिला प्रशासन की इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू **मानव संसाधन को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना** है। AI जैसे आधुनिक उपकरणों की जानकारी सीधे प्रशासनिक अमले तक पहुंचने से सरकारी कामकाज में तकनीकी दक्षता विकसित होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी नहीं दी गई, बल्कि **Hands-on Practical Sessions** के माध्यम से AI टूल्स का व्यावहारिक उपयोग भी कराया गया। इसका उद्देश्य था कि अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण में सीखी तकनीकों को अपने रोजमर्रा के कार्यों में उपयोग कर सकें।

प्रशिक्षण से लेकर प्रयोग तक

JSLPS एवं GDI Partners के तकनीकी विशेषज्ञों ने AI की अवधारणा, विभिन्न उपयोगों और सरकारी कार्यों में इसकी संभावनाओं पर प्रशिक्षण दिया। GDI के विशेषज्ञ **श्री अंशुल गुप्ता** और **सुश्री जान्हवी बहादुर** ने प्रशिक्षण सत्रों का संचालन एवं तकनीकी मार्गदर्शन किया। JSLPS के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इससे यह संदेश भी सामने आया कि प्रशासनिक व्यवस्था में तकनीकी बदलाव केवल नीतियों तक सीमित न रहकर **अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि** से भी जुड़ रहा है।

नागरिक सुविधा को केंद्र में रखकर तकनीकी बदलाव

AI का प्रशासन में उपयोग तभी सार्थक है, जब उसका अंतिम लाभ आम नागरिक तक पहुंचे। दस्तावेजों के प्रबंधन से लेकर सूचनाओं के विश्लेषण, कार्यों की प्राथमिकता तय करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने तक AI भविष्य में अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। सिमडेगा की पहल इसी व्यापक सोच को सामने रखती है— **तकनीक को कार्यालय की सुविधा नहीं, बल्कि नागरिक सेवा की ताकत बनाना।**

एक पहल, जो दूसरे जिलों के लिए बन सकती है प्रेरणा

सिमडेगा जिला प्रशासन द्वारा AI प्रशिक्षण की यह पहल प्रशासनिक नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखी जा सकती है। यह दिखाती है कि छोटे जिलों में भी आधुनिक तकनीक को अपनाकर प्रशासनिक क्षमता को नई दिशा दी जा सकती है। ■

सिमडेगा ने AI को केवल तकनीक के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि उसे प्रशासनिक दक्षता, क्षमता निर्माण और बेहतर नागरिक सेवा से जोड़ने की पहल की है। यही सोच आने वाले समय के 'स्मार्ट और संवेदनशील प्रशासन' की मजबूत आधारशिला बन सकती है।



नोएडा का नया विकास मॉडल

उद्योग, नागरिक सुविधाओं और किसान हितों के साथ आगे बढ़ता शहर

आर्थिक मजबूती से लेकर स्वच्छता, हरियाली और नागरिक सुविधाओं तक—विकास की दिशा में बड़े फैसलों ने दिखाई नई तस्वीर

तेजी से बदलते शहरी भारत की पहचान बन चुका नोएडा अब केवल आधुनिक इमारतों, चौड़ी सड़कों और औद्योगिक गतिविधियों का शहर नहीं रह गया है। विकास की नई सोच में **आर्थिक मजबूती, नागरिक सुविधाओं की दीर्घकालिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक सुगमता और किसानों की भागीदारी** को एक साथ जोड़ने का प्रयास दिखाई दे रहा है। 5 सितंबर 2026 को आयोजित नोएडा प्राधिकरण की 223वीं बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इसी व्यापक दृष्टिकोण की ओर संकेत करते हैं।

आज की जरूरतों के साथ भविष्य की सुविधाओं की भी चिंता

नोएडा के दीर्घकालिक विकास में केवल नई परियोजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है। पानी की आपूर्ति, सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक अवस्थापना जैसी बुनियादी सेवाओं का निरंतर और मजबूत संचालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से **One-Time Lease Rent–Corpus Fund (OTLR-CF)** की Standard Operating Procedures को स्वीकृति दी गई है।

इस व्यवस्था के माध्यम से एकमुश्त गैर-आवर्ती आय का व्यवस्थित लेखांकन, निवेश, उपयोग और निगरानी की व्यवस्था विकसित होगी, जिससे भविष्य में शहर की आवश्यक नागरिक सेवाओं के रखरखाव को आर्थिक आधार मिल सकेगा।



रुकी परियोजनाओं को गति, घर खरीदारों को राहत

रियल एस्टेट क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को गति देना भी इस बैठक का महत्वपूर्ण पहलू रहा। 36 परियोजनाओं से अब तक **540.75 करोड़** तथा अन्य आंशिक भुगतानों सहित कुल **561.35 करोड़** जमा होने की जानकारी दी गई। लंबित परियोजनाओं में वसूली तथा फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह कदम उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी वर्षों की बचत घर मिलने की प्रतीक्षा में अटकी हुई है। परियोजनाओं को गति मिलने

से आवासीय बाजार में भरोसा मजबूत होने के साथ-साथ खरीदारों को संपत्ति के वैध दस्तावेज प्राप्त करने का रास्ता भी आसान होगा।

उद्योगों के लिए 'एकरूप नीति', निवेश के लिए बेहतर माहौल

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक गतिविधियों को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से Unified Regulations, 2025 से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए **एकरूप नीति** की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है।

ट्रांसफर शुल्क, औद्योगिक इकाइयों को क्रियाशील करने की समय-सीमा तथा अन्य शुल्क और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत एवं एकरूप बनाने के लिए दोनों प्राधिकरणों के अधिकारियों की समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ऐसी व्यवस्था से उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं में स्पष्टता बढ़ सकती है और औद्योगिक निवेश के वातावरण को मजबूती मिल सकती है।

कचरे से ऊर्जा : स्वच्छ नोएडा की दिशा में बड़ा कदम

शहरी विकास की सबसे बड़ी चुनौतियों में ठोस कचरा प्रबंधन भी शामिल है। नोएडा में सूखे/RDF कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए सेक्टर-145 में ***100 TPD क्षमता वाली Thermolysis आधारित Integrated Waste-to-Energy and Resource Recovery Facility*** स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

कचरे को केवल निस्तारित करने के बजाय उससे ऊर्जा और संसाधन प्राप्त करने की दिशा में यह पहल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को अधिक आधुनिक और टिकाऊ बनाने की क्षमता रखती है।

हरियाली को आधुनिक स्वरूप देने की पहल

सेक्टर-8 की लगभग 8 एकड़ नर्सरी को Build-up, Operation and Maintenance (BOM) मॉडल पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उद्देश्य





इसे आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों की एकीकृत सुविधा के रूप में विकसित करना है।

यह पहल नोएडा की पहचान को केवल 'कंक्रीट सिटी' के बजाय हरित और रहने योग्य शहर के रूप में मजबूत करने में योगदान दे सकती है।

किसानों की भागीदारी को विकास से जोड़ने का प्रयास

नोएडा के विकास में भूमि देने वाले किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बोर्ड ने आपसी समझौते के आधार पर भूमि खरीद के लिए मुआवजा दर को **6,459 प्रति वर्ग मीटर** तथा 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड के लाभ से जोड़ने के प्रस्ताव पर सहमति दी है।

इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि किसानों को केवल भूमि का मूल्य देने तक सीमित न रखकर उन्हें नोएडा और न्यू नोएडा के विकास तथा भविष्य की आर्थिक समृद्धि में सहभागी बनाने की सोच सामने आती है।

विकास का अर्थ केवल निर्माण नहीं—सुविधा, विश्वास और सहभागिता भी

नोएडा प्राधिकरण की 223वीं बोर्ड बैठक के निर्णयों को समग्र रूप से देखें तो इनके केंद्र में एक ऐसा शहर बनाने की सोच दिखाई देती है, जहां **उद्योगों को गति मिले, नागरिक सुविधाएं टिकाऊ बनें, पर्यावरण को प्राथमिकता मिले, लंबित आवासीय परियोजनाओं को राहत मिले और किसानों की भागीदारी विकास की प्रक्रिया से जुड़ी रहे।**

यही संतुलित दृष्टिकोण नोएडा को भविष्य के ऐसे आधुनिक शहर की दिशा में आगे ले जा सकता है, जहां विकास केवल दिखाई ही न दे, बल्कि उसका लाभ **उद्योग, नागरिक, किसान और आने वाली पीढ़ियां—सभी महसूस कर सकें।** ■



खेत से बाजार तक डिजिटल सुरक्षा कवच: 'मनोरमा कृषि रक्षक' से किसानों को नई तकनीकी ताकत

उत्तराखंड में कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान-केंद्रित मोबाइल एप **'मनोरमा कृषि रक्षक'** का शुभारंभ किया है। यह एप केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि किसानों को **मौसम, फसल, रोग, बाजार और लॉजिस्टिक्स** जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों एवं सेवाओं से जोड़ने का एक समग्र प्रयास है।

आज कृषि क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। बदलते मौसम, फसलों में बीमारियों की चुनौती, बाजार की सही जानकारी और उत्पाद को समय पर उचित स्थान तक पहुंचाने जैसी समस्याएं किसानों के सामने अक्सर बड़ी चुनौती बनती हैं। ऐसे समय में 'मनोरमा कृषि रक्षक' जैसे डिजिटल मंच किसानों के लिए एक उपयोगी सहयोगी के रूप में उभर सकते हैं।

एप के माध्यम से किसानों को **रियल टाइम मौसम संबंधी जानकारी और अलर्ट, फसल-विशिष्ट कृषि सलाह तथा एआई आधारित फसल रोग पहचान** जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इससे किसान समय रहते संभावित समस्याओं को समझकर बेहतर निर्णय ले सकेंगे। आधुनिक तकनीक का यह उपयोग खेती को अधिक



वैज्ञानिक, सुरक्षित और लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस पहल की एक विशेषता यह भी है कि इसमें **कृषि एवं बाजार संबंधी जानकारी के साथ परिवहन और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं** को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य किसान को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उसके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया में भी डिजिटल सहयोग प्रदान करना है।

'मनोरमा कृषि रक्षक' एप में **स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमों को बाजार से जोड़ने** की सुविधा भी शामिल की गई है। यह ग्रामीण महिलाओं और छोटे उद्यमियों के लिए नए आर्थिक अवसरों के द्वार खोल सकता है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल को किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग से कृषि संबंधी आवश्यक जानकारियां और सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। वास्तव में, यह पहल उस बदलते भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है, **जहां खेत और तकनीक का मिलन किसान की मेहनत को नई शक्ति दे रहा है।** 'मनोरमा कृषि रक्षक' जैसे प्रयास भविष्य में कृषि को अधिक स्मार्ट, सुलभ और बाजारोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ■

जब सरकारी संबल बना हुनर की ताकत

महतारी वंदन योजना से गंडई की कंडरा समाज की महिलाओं ने बांस शिल्प को दी नई उड़ान

आत्मनिर्भरता की राह हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि उपलब्ध अवसरों और अपने हुनर के सही इस्तेमाल से भी बनती है। छत्तीसगढ़ की **महतारी वंदन योजना** से जुड़ी गंडई की कंडरा समाज की महिलाओं की कहानी इसी सोच को साकार करती है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को उन्होंने अपनी पारंपरिक आजीविका से जोड़कर बांस शिल्प को आगे बढ़ाने का माध्यम बनाया है।

नगर पंचायत गंडई के वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाली कंडरा समाज की महिलाएं लंबे समय से बांस शिल्प से जुड़ी हैं। बांस से टोकरी, सूपा और अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार करना उनके पारंपरिक कौशल और आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता ने उनके लिए इस काम को जारी रखने में आर्थिक संबल प्रदान किया है।

योजना की राशि से खरीदा बांस, हुनर से तैयार हुए उत्पाद

महिलाएं योजना से प्राप्त राशि का उपयोग बांस खरीदने में कर रही हैं। इसके बाद अपने पारंपरिक कौशल और अनुभव के आधार पर बांस से टोकरी, सूपा तथा अन्य उपयोगी सामग्री तैयार करती हैं।

यह प्रक्रिया अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है—आर्थिक सहायता का उपयोग केवल खर्च के लिए ही नहीं, बल्कि **आय सृजन से जुड़ी गतिविधि को आगे बढ़ाने** में भी किया जा रहा है।

बांस से तैयार इन उत्पादों को महिलाएं स्थानीय स्तर पर बेचती हैं। बिक्री से उन्हें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है, जिससे उनके आर्थिक योगदान और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलती है।

परंपरा से जुड़ा हुनर, भविष्य से जुड़ी उम्मीद

कंडरा समाज के लिए बांस शिल्प केवल एक काम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा पारंपरिक कौशल है। आधुनिक समय में पारंपरिक व्यवसायों के सामने बाजार और संसाधनों से जुड़ी कई चुनौतियां रहती हैं। ऐसे में नियमित आर्थिक सहायता इस हुनर को जारी रखने के लिए उपयोगी आधार बन सकती है।

गंडई की इन महिलाओं ने इसी अवसर को अपनी मेहनत से जोड़ा है। योजना से मिला आर्थिक संबल बांस की खरीद में लगाया गया और उस बांस को उनके हाथों ने उपयोगी उत्पादों का रूप दिया। इस तरह **सरकारी सहायता, पारंपरिक कौशल और मेहनत** एक-दूसरे से जुड़कर आय का माध्यम बन रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण की जमीनी तस्वीर

महतारी वंदन योजना से जुड़ी यह पहल महिला सशक्तिकरण की उस तस्वीर को सामने लाती है, जिसमें महिलाएं अपनी पारंपरिक दक्षता के आधार पर आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। गंडई की कंडरा समाज की महिलाओं ने योजना की सहायता को अपने हुनर से जोड़कर उसे एक अवसर का रूप दिया है। उनकी यह पहल बताती है कि यदि आर्थिक सहयोग के साथ महिलाओं को अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने का अवसर मिले, तो पारंपरिक आजीविका भी आत्मनिर्भरता का आधार बन सकती है।

बांस के उत्पादों में बुनी आत्मनिर्भरता

वार्ड क्रमांक 12 की इन महिलाओं की कहानी में सबसे खास बात यह है कि उनके हाथों में मौजूद पारंपरिक हुनर को आर्थिक सहयोग का आधार मिला। बांस की साधारण सी डंडी से टोकरी और सूपा जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार होते हैं और फिर यही उत्पाद स्थानीय बाजार में उनकी आमदनी का माध्यम बनते हैं।

महतारी वंदन योजना ने उन्हें आर्थिक संबल दिया और महिलाओं ने अपने हुनर व मेहनत से उसे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया।

गंडई की यह कहानी बताती है कि जब **सरकारी सहयोग पारंपरिक कौशल और मेहनत से जुड़ता है, तो आत्मनिर्भरता की राह गांव की चौखट से ही शुरू हो सकती है।** ■





सरकारी खरीद से ग्लोबल मार्केट तक— एमएसएमई के लिए नए अवसरों का द्वार

गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय कार्यशाला ने उद्यमियों को दिया विस्तार, निर्यात और रोजगार का नया विजन

किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की असली ताकत केवल बड़े उद्योगों में नहीं, बल्कि उन हजारों छोटे और मध्यम उद्यमों में होती है जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन, रोजगार और नवाचार की नई कहानी लिखते हैं। **गौतमबुद्धनगर ने अब इसी एमएसएमई शक्ति को नए बाजारों, सरकारी खरीद और निर्यात के अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है।** आईआईएलएम विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में आयोजित वन डे नेशनल वर्कशॉप ऑन प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट (PMS) स्कीम ने स्थानीय उद्यमियों को सरकारी खरीद से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने का व्यावहारिक मार्ग दिखाया।

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय (डीएफओ), ओखला, नई दिल्ली तथा आईआईएलएम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन (आईबीए) की पहल पर आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में **150 से अधिक उद्यमियों** ने सहभागिता की। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया।

'बड़ा सोचें, बड़े बाजार तक पहुंचें'—उद्यमियों को जिलाधिकारी का संदेश

कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने गौतमबुद्धनगर को औद्योगिक विकास, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और निवेश के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ केंद्र बताते हुए उद्यमियों से अपने व्यवसाय को स्थानीय बाजार तक सीमित न रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि **उद्यमियों को बड़ा सपना देखना चाहिए और अपने उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए।**

उनका संदेश केवल कारोबार बढ़ाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने उद्यमियों को रोजगार सृजन और सामाजिक उत्तरदायित्व से भी जोड़ते हुए कहा कि उद्योगों की सफलता का वास्तविक अर्थ तब और व्यापक हो जाता है, जब उससे युवाओं को रोजगार मिले और समाज को उसका लाभ पहुंचे।

सरकारी खरीद बनी एमएसएमई के लिए बड़ा अवसर

कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि उद्यमियों को सरकारी खरीद की पूरी प्रक्रिया से परिचित कराया गया। **GeM पोर्टल, विक्रेता पंजीकरण, सरकारी विभागों में खरीद की प्रक्रिया, PMS योजना, विपणन सहायता और निर्यात संवर्धन** जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

एमएसएमई के लिए सरकारी खरीद एक बड़ा और स्थायी बाजार उपलब्ध करा सकती है। ऐसे में योजनाओं और प्रक्रियाओं की सही जानकारी छोटे उद्यमों को बड़े खरीदारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।



लोकल उद्यम से ग्लोबल ब्रांड बनने की राह

आज गौतमबुद्धनगर केवल औद्योगिक उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि **इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, विनिर्माण और निवेश के नए अवसरों का प्रमुख क्षेत्र** बन रहा है। ऐसे वातावरण में एमएसएमई को डिजिटल मार्केटिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, निर्यात और आधुनिक विपणन तकनीकों से जोड़ना उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

विशेषज्ञों ने उद्यमियों को उपलब्ध सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नए बाजार तलाशने और अपने उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

सरकार–उद्योग–शिक्षा जगत की साझेदारी का मॉडल

इस आयोजन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि **सरकार, उद्योग संगठन और विश्वविद्यालय के बीच बनी त्रिस्तरीय साझेदारी** भी रही। आईबीए ने जहां उद्योग जगत की जरूरतों को मंच प्रदान किया, वहीं एमएसएमई मंत्रालय ने योजनाओं और सरकारी खरीद की जानकारी उपलब्ध कराई तथा आईआईएलएम विश्वविद्यालय ने आयोजन के लिए शैक्षणिक एवं संस्थागत मंच उपलब्ध कराया।

यह साझेदारी बताती है कि जब **नीति, उद्योग और ज्ञान** एक मंच पर आते हैं, तो उद्यमिता के लिए नए रास्ते खुलते हैं।

एमएसएमई को नई उड़ान देने की दिशा में सार्थक पहल

गौतमबुद्धनगर की औद्योगिक पहचान को और मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी को उद्यमियों तक पहुंचाना, उन्हें सरकारी खरीद से जोड़ना, नए बाजारों की तलाश में मार्गदर्शन देना और निर्यात के लिए तैयार करना—ये सभी कदम **स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत आधार** तैयार करते हैं।

आईबीए, एमएसएमई मंत्रालय और आईआईएलएम विश्वविद्यालय की यह पहल इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक कार्यशाला तक सीमित नहीं, बल्कि **'लोकल उद्यम से राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार से ग्लोबल मार्केट'** की ओर बढ़ने की सोच को प्रोत्साहित करती है। ■

गौतमबुद्धनगर में एमएसएमई के लिए संदेश स्पष्ट है—अवसर मौजूद हैं, बाजार व्यापक है और अब जरूरत है उन्हें पहचानकर बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की।



जल सहयोग की ऐतिहासिक पहल

किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध से छह राज्यों की विकास यात्रा को मिलेगा नया आधार

भारत में नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था और विकास की आधारशिला हैं। ऐसे में जब अलग-अलग राज्य साझा जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए साथ आते हैं, तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा से भी जुड़ जाता है। **किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना** को लेकर हुआ समझौता इसी व्यापक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री **श्री अमित शाह** की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री **श्री सी.आर. पाटिल** के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते में भागीदारी की।

छह राज्यों के लिए साझा जल संसाधन

परियोजना का महत्व इसलिए भी व्यापक है क्योंकि इससे संबंधित राज्यों में **पेयजल, सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं** के लिए जल उपलब्धता को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। जल संसाधनों का समुचित और समन्वित उपयोग कृषि, उद्योग, शहरी आवश्यकताओं तथा क्षेत्रीय विकास के लिए आधार तैयार कर सकता है।



राजस्थान के मुख्यमंत्री **श्री भजनलाल शर्मा** ने समझौते को राज्यों के बीच आपसी सहयोग की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि राज्यों की सहमति और सहयोग से लंबे समय से लंबित परियोजनाओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

जल समझौते और विकास की नई संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने राजस्थान के संदर्भ में यमुना जल समझौते, रामजल सेतु लिंक परियोजना, नर्मदा जल समझौते और किशाऊ बांध परियोजना को महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया। उनके अनुसार ऐसे समझौते राज्य की दीर्घकालिक **जल सुरक्षा** के लिए महत्वपूर्ण हैं।

किशाऊ परियोजना से जुड़े छह राज्यों के बीच समन्वय का व्यापक उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए विभिन्न





क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना है। इससे कृषि क्षेत्र को सिंचाई का आधार, शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल का सहारा तथा विकास गतिविधियों को आवश्यक जल संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिल सकती है।

साझा प्रयास, साझा भविष्य

किशाऊ समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राज्यों के बीच सहयोग की भावना है। जल जैसे सीमित और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के लिए संवाद, सहमति और समन्वय की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।

यह पहल इस बात का उदाहरण भी है कि जब विभिन्न राज्य साझा आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ते हैं, तो लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को गति देने की संभावनाएं बनती हैं। **जल सुरक्षा केवल आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और संतुलित विकास की बुनियाद है।**

छह राज्यों की भागीदारी वाला यह समझौता इसी सोच को आगे बढ़ाता है— **साझा जल संसाधन, साझा जिम्मेदारी और साझा विकास।** ■

हरित क्रांति के शिल्पकार: प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन

जिस वैज्ञानिक दृष्टि ने भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता की राह दिखाई



प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन भारत के उन महान वैज्ञानिकों में शामिल हैं, जिन्होंने कृषि विज्ञान को किसानों की शक्ति और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा से जोड़ा। हरित क्रांति के दौर में उनके वैज्ञानिक नेतृत्व और दूरदर्शी सोच ने भारत के कृषि परिदृश्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऐसे समय में जब देश खाद्यान्न की कमी और आयात पर निर्भरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था, स्वामीनाथन ने आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीजों और वैज्ञानिक अनुसंधान को खेतों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उनके प्रयासों ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और भारत को खाद्य सुरक्षा की मजबूत राह पर आगे बढ़ाने में योगदान दिया।

हरित क्रांति के इस महान शिल्पकार को स्मरण करना भारत की कृषि आत्मनिर्भरता की उस यात्रा को नमन करना है, जिसने देश को संकट से आत्मविश्वास और खाद्य सुरक्षा की ओर अग्रसर किया।

लेकिन उनका विजन केवल अधिक उत्पादन तक सीमित नहीं था। वे **किसान कल्याण, पोषण सुरक्षा, महिला किसानों की भागीदारी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण** को भी कृषि विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने **'एवरग्रीन रिवोल्यूशन'** की अवधारणा को आगे बढ़ाया—ऐसी कृषि क्रांति जो उत्पादन बढ़ाने के साथ पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे।

आज जलवायु परिवर्तन, जल संकट और टिकाऊ कृषि की बढ़ती आवश्यकता के बीच प्रो. स्वामीनाथन की विचारधारा और अधिक प्रासंगिक हो गई है।

प्रेरणा की अमर विरासत

प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की विरासत हमें यह संदेश देती है कि **विज्ञान की वास्तविक सफलता तभी है, जब उसका लाभ किसान और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।** ■

हुनर को सम्मान, मेहनत को पहचान

हरियाणा में सशक्त कारीगर से सशक्त प्रदेश की ओर कदम

महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, नवाचार और श्रमिक कल्याण को एक साथ जोड़ती पहलें; दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार से 17 लाख और महिलाओं को लाभ की उम्मीद

विकास की असली तस्वीर केवल बड़ी परियोजनाओं, आधुनिक सड़कों और औद्योगिक इकाइयों में नहीं दिखाई देती, बल्कि उस बदलाव में दिखाई देती है जो किसी महिला को आर्थिक संबल देता है, किसी कारीगर के हुनर को बाजार से जोड़ता है, किसी युवा के विचार को नवाचार का अवसर देता है और किसी श्रमिक के जीवन में सामाजिक सुरक्षा का भरोसा पैदा करता है। हरियाणा में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ऐसी ही अनेक पहलों को एक साथ आगे बढ़ाने का संदेश सामने आया।

मुख्यमंत्री **नायब सिंह सैनी ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना** के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए योजना के लिए पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा को **1 लाख रुपये** से बढ़ाकर **1.80 लाख रुपये** करने की घोषणा की। इसके तहत पात्र महिलाओं को **2,100 रुपये प्रतिमाह** का लाभ मिलेगा। पहले चरण में 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की 10 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। आय सीमा बढ़ाए जाने के बाद लगभग **17 लाख अतिरिक्त महिलाओं** को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य है।



महिला से परिवार और परिवार से अर्थव्यवस्था तक

महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली योजनाएं परिवार की आर्थिक क्षमता को मजबूत करने के साथ महिलाओं की वित्तीय भागीदारी को भी बढ़ा सकती हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार को इसी व्यापक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। आर्थिक सहयोग का यह आधार महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा और परिवार की प्राथमिकताओं में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर दे सकता है।

'मेरा हुनर, मेरी पहचान' की नई सोच

भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कारीगरों, शिल्पकारों और श्रमिकों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि **हुनर को सम्मान, मेहनत को पहचान और कारीगर को आगे बढ़ने के अवसर** मिलें।

हरियाणा की औद्योगिक विकास यात्रा में पारंपरिक कारीगरों और श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में







पारंपरिक कौशल को नई तकनीक, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ना इस वर्ग की आय एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।

PM विश्वकर्मा से कौशल को बाजार तक पहुंच

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण अवधि में प्रतिदिन **500 रुपये का स्टाइपेंड,** आधुनिक टूलकिट के लिए सहायता तथा बिना जमानत ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुंच बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

राज्य सरकार के अनुसार हरियाणा में योजना के तहत **41,366 आवेदक पंजीकृत,** 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण पूर्ण और लगभग 12 हजार कारीगरों को टूलकिट उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। लगभग 6 हजार कारीगरों को 56 करोड़ रुपये के ऋण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

युवा सोच को मिलेगा नवाचार का मंच

कार्यक्रम में **'SEVA First Innovation Challenge'** पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और आम नागरिकों को अपने अभिनव विचार, तकनीक, उत्पाद एवं समाधान प्रस्तुत करने का अवसर देना है।

प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक जिले से चयनित श्रेष्ठ नवाचार को **1 लाख रुपये** तथा राज्य स्तर पर चुने गए शीर्ष तीन नवाचारों को **5 लाख रुपये** की पुरस्कार राशि और विशेष सम्मान देने की व्यवस्था की गई है। ऐसी पहलें युवाओं को केवल रोजगार तलाशने के बजाय समस्याओं के समाधान और नए अवसरों के सृजन की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।

खेल और श्रमिक कल्याण को भी प्राथमिकता

कार्यक्रम में **3,396 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों** को खेल गतिविधियों के लिए कुल **33.96 करोड़ रुपये** की अनुदान राशि जारी की गई। प्रत्येक विद्यालय को एक लाख रुपये की राशि दी गई।

वहीं औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत **64,783 श्रमिकों** के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं के तहत **48.91 करोड़ रुपये** की राशि जारी की गई। निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन, दिव्यांगता सहायता, दुर्घटना एवं मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहयोग तथा सिलिकोसिस प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास जैसी व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया।

कौशल आधारित शिक्षा का मजबूत आधार

मुख्यमंत्री ने पलवल के दुधौला स्थित **श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय** को कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट मॉडल के रूप में विकसित किए जाने की बात कही। कौशल विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल युवाओं को रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में उपयोगी हो सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री **कुमारी आरती सिंह राव** ने भी कारीगरों और श्रमिकों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य हर हुनर को सम्मान, हर मेहनत को पहचान और हर हाथ को आगे बढ़ने का अवसर देना है। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं की भी जानकारी दी।

विकास का अर्थ— अवसरों का विस्तार

हरियाणा में इन पहलों की तस्वीर को एक साथ देखें तो इसके केंद्र में केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि **अवसरों का विस्तार** दिखाई देता है—महिलाओं के लिए आर्थिक सहयोग, युवाओं के लिए नवाचार का मंच, कारीगरों के लिए कौशल और वित्तीय सहायता, विद्यार्थियों के लिए खेल सुविधाएं तथा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा।

यही वह दृष्टिकोण है जिसमें विकास को केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि **हुनर, मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास** से जोड़ा जाता है। जब किसी कारीगर को अपने कौशल के साथ बाजार मिलता है, युवा को अपने विचार को आकार देने का अवसर मिलता है और महिला को आर्थिक निर्णयों में अधिक भागीदारी का आधार मिलता है, तब विकास की प्रक्रिया समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंचती है। ■

हर हाथ में हुनर, हर हुनर को अवसर और हर मेहनत को सम्मान—यही सोच आत्मनिर्भर और सशक्त हरियाणा की दिशा को नई ऊर्जा दे सकती है।



कलम की संवेदना, प्रशासन का संकल्प

ललित मोहन रयाल : साहित्यिक चेतना से समृद्ध एक प्रशासक की जनसेवा यात्रा

किसी जिले का प्रशासन केवल सरकारी आदेशों और फाइलों से नहीं चलता। उसके पीछे होती है— **दृष्टि, निर्णय क्षमता, संवाद और सबसे बढ़कर मानवीय संवेदना।** जब किसी प्रशासक के व्यक्तित्व में साहित्य और समाज को करीब से देखने की दृष्टि भी जुड़ जाए, तो उसकी कार्यशैली को समझने का एक नया आयाम सामने आता है।

नैनीताल के जिलाधिकारी **श्री ललित मोहन रयाल** का व्यक्तित्व इसी संगम का परिचय देता है। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साहित्य के प्रति उनकी गहरी रुचि और लेखन-यात्रा उन्हें एक ऐसे प्रशासक के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसके व्यक्तित्व में **अधिकारी की जिम्मेदारी और लेखक की संवेदना** साथ-साथ दिखाई देती है।

नैनीताल जैसे भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं वाले जनपद की जिम्मेदारी संभालना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। पर्यटन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, राजस्व, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े अनेक विषय एक साथ प्रशासन की प्राथमिकताओं में रहते हैं। ऐसे परिवेश में जनता से संवाद और समस्याओं के समाधान की कार्यशैली विशेष महत्व रखती है।

पद के पीछे छिपा एक संवेदनशील लेखक

ललित मोहन रयाल की पहचान केवल एक प्रशासनिक अधिकारी तक सीमित नहीं है। उनकी साहित्यिक यात्रा भी उल्लेखनीय है। उपलब्ध साहित्यिक परिचयों के अनुसार उन्होंने अब तक **पांच पुस्तकों** की रचना की है—**'खड़गमाफी की स्मृतियों से', 'अथ श्री प्रयाग कथा', 'चाकरी चतुरंग', 'कारी तू कभी ना हारी' और 'कल फिर जब सुबह होगी'।**

इन पांचों कृतियों को देखें तो लेखक रयाल की रुचियों का एक व्यापक संसार सामने आता है—स्मृतियां, समाज, व्यवस्था, परिवार, लोकजीवन और उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना।

उनकी पांचवीं पुस्तक **'कल फिर जब सुबह होगी'** विशेष रूप से उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और लोकगायन से जुड़ती है। पुस्तक में लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के 101 प्रतिनिधि गीतों का चयन, हिंदी अनुवाद और व्याख्या के माध्यम से पर्वतीय समाज और उसकी संवेदनाओं को समझने का प्रयास किया गया है।

यह कार्य केवल साहित्यिक अभिरुचि का परिचय नहीं देता, बल्कि उस समाज और संस्कृति के प्रति जुड़ाव को भी सामने लाता है, जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान है।

'चाकरी चतुरंग' : व्यवस्था को भीतर से देखने वाली दृष्टि

रयाल की पुस्तक **'चाकरी चतुरंग'** उनके लेखकीय व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष सामने लाती है। सरकारी व्यवस्था और राजकीय सेवा के अनुभवों को साहित्यिक और व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखने वाली यह कृति व्यवस्था के भीतर के व्यवहार और कार्यसंस्कृति पर ध्यान आकर्षित करती है।

एक लोकसेवक के रूप में व्यवस्था को भीतर से देखने और लेखक के रूप में उसी व्यवस्था पर कलम चलाने का यह मेल उनके व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाता है।

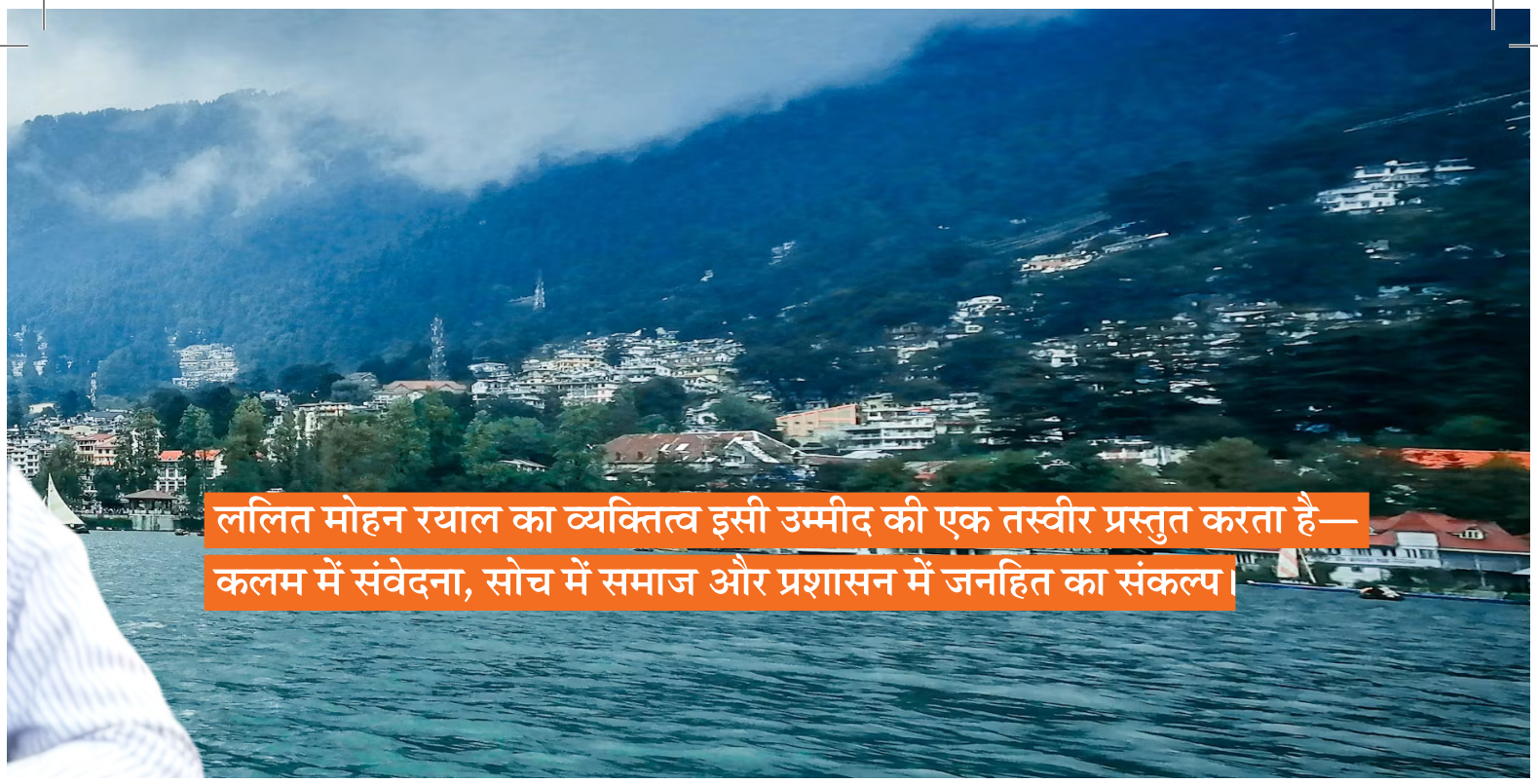
यहां लेखक व्यवस्था से अलग खड़ा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर रहकर उसे समझने वाला व्यक्ति है।

'कारी तू कभी ना हारी' : रिश्तों और संस्कारों की कहानी

रयाल के व्यक्तित्व का सबसे भावनात्मक पक्ष उनकी पुस्तक **'कारी तू कभी ना हारी'** में दिखाई देता है। यह उनके पिता स्वर्गीय मुकुंद राम रयाल के जीवन पर आधारित कृति है।

एक शिक्षक के संघर्ष, जीवन-मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों को शब्द देना केवल साहित्यिक कार्य नहीं, बल्कि स्मृतियों और रिश्तों को सम्मान देने का माध्यम भी है।

इस पुस्तक के माध्यम से लेखक का वह पक्ष सामने आता है जहां प्रशासनिक पद और अधिकार पीछे छूट जाते हैं और सामने आता है— **एक पुत्र, अपने पिता के जीवन-संघर्ष को समझता और उसे शब्द देता हुआ।**



ललित मोहन रयाल का व्यक्तित्व इसी उम्मीद की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है— कलम में संवेदना, सोच में समाज और प्रशासन में जनहित का संकल्प।

'अथ श्री प्रयाग कथा' और 'खड़गमाफी की स्मृतियों से'

'अथ श्री प्रयाग कथा' में शहर, समाज और समय को देखने की दृष्टि दिखाई देती है, जबकि **'खड़गमाफी की स्मृतियों से'** स्मृतियों और अपने परिवेश से जुड़ने वाली रचना के रूप में सामने आती है।

इन रचनाओं को पढ़ते हुए यह महसूस किया जा सकता है कि रयाल की लेखनी का केंद्र केवल घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे मौजूद **मनुष्य और उसका परिवेश है।**

यही संवेदनशील दृष्टि किसी भी सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है।

जनता से संवाद—प्रशासन की पहली कड़ी

नैनीताल में कार्यभार संभालने के दौरान रयाल ने अधिकारियों को जनता से संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ करने पर जोर दिया।

यह सोच प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी कार्यालय जनता के लिए हैं और प्रशासन की सार्थकता तभी बढ़ती है, जब नागरिक को अपनी बात रखने और उसके समाधान की प्रक्रिया में विश्वास महसूस हो।

रयाल की कार्यशैली में **संवाद को प्राथमिकता** देने का यह पहलू उनकी साहित्यिक संवेदना के साथ भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है।

फाइलों से आगे—समस्या के पीछे के व्यक्ति तक

राजस्व और भूमि से जुड़े मामलों को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों के नागरिकों के सामने अक्सर व्यावहारिक कठिनाइयां रहती हैं। नामांतरण, विरासत, सीमांकन और अभिलेखों से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण होता है।

जिले में प्रशासनिक पहल का असर राजस्व एवं नागरिक सेवाओं के निस्तारण में दिखाई दे रहा है।

नैनिताल जिला प्रशासन द्वारा आयोजित चौपालों के माध्यम से 33,552 वारिसानों/ लाभार्थियों के नाम विरासत में दर्ज किए गए। राजस्व प्रकृति के विवादों के समाधान के लिए गठित समिति ने 5,444 मामलों का निस्तारण किया गया, कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में भी 576 वादों का निस्तारण हुआ। नागरिक सेवाओं में जन्म प्रमाणपत्र के 97 प्रतिशत तथा मृत्यु प्रमाणपत्रों के 100 प्रतिशत आवेदन निस्तारित किए गए। ये प्रयास प्रशासन और आमजन के बीच भरोसे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

यह आंकड़े प्रशासनिक कार्य की मात्रा बताते हैं, लेकिन हर मामले के पीछे किसी परिवार की उम्मीद और आवश्यकता जुड़ी होती है। यही वह स्थान है जहां प्रशासनिक दक्षता और मानवीय संवेदना एक-दूसरे से जुड़ती हैं।

गांव, किसान और जमीन से जुड़ता प्रशासन

प्रशासन की वास्तविक पहुंच तब दिखाई देती है, जब अधिकारी सरकारी भवनों से निकलकर गांवों और खेतों तक पहुंचते हैं।

रयाल द्वारा किसान के खेत में पहुंचकर क्रॉप कटिंग में भाग लेने की तस्वीर भी इसी तरह की प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाती है। किसान के बीच पहुंचना केवल एक औपचारिक गतिविधि नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़े विषयों को जमीन के स्तर पर समझने का अवसर भी है।

कृषि, ग्रामीण विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखने वाली ऐसी पहलें प्रशासन को समाज के अधिक करीब लाती हैं।

नैनीताल की चुनौतियां और प्रशासन की जिम्मेदारी

नैनीताल की पहचान पर्यटन से है, लेकिन इसकी प्रशासनिक चुनौतियां इससे कहीं व्यापक हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक कठिनाइयां, मानसून और भूस्खलन का जोखिम, पर्यटन का दबाव, यातायात, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों

में मूलभूत सुविधाएं तथा भूमि और राजस्व से जुड़े मामले—इन सभी के बीच प्रशासन को विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होता है।

जिला प्रशासन की भूमिका ऐसे में केवल योजनाओं को लागू करने तक सीमित नहीं रहती। **आपदा के समय तत्परता, सामान्य दिनों में नागरिक सेवाओं की उपलब्धता और विकास के दौरान स्थानीय जरूरतों की समझ** —ये सभी सुशासन के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

लेखक और प्रशासक—दो अलग भूमिकाएं, एक ही सरोकार

रयाल की साहित्यिक यात्रा और प्रशासनिक भूमिका को साथ रखकर देखने पर एक दिलचस्प समानता दिखाई देती है।

साहित्य में वे **लोकजीवन, समाज, व्यवस्था और मनुष्य** को देखते हैं।

प्रशासन में भी केंद्र में वही समाज और वही मनुष्य होता है।

उनकी पुस्तकों में कभी स्मृतियां बोलती हैं, कभी व्यवस्था पर व्यंग्य होता है, कभी पिता के संघर्ष की कहानी सामने आती है और कभी पहाड़ के लोकगीतों में समाज की आवाज सुनाई देती है।

यानी उनकी लेखनी का मूल सरोकार **मनुष्य और समाज** से जुड़ा दिखाई देता है।

संवेदना से सुशासन तक

आज के दौर में प्रशासन से केवल निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं है। नागरिक चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी समस्या को समझा जाए और उसे समाधान की स्पष्ट दिशा मिले।

इसीलिए प्रशासनिक कार्यशैली में संवेदनशीलता का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

ललित मोहन रयाल के व्यक्तित्व का साहित्यिक पक्ष इस संदर्भ में विशेष रुचि पैदा करता है। एक लेखक के रूप में समाज को देखने का अनुभव और एक प्रशासक के रूप में समाज के लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी—दोनों भूमिकाएं उनके व्यक्तित्व में साथ दिखाई देती हैं।

पांच किताबें—एक व्यापक व्यक्तित्व

खड़गमाफी की स्मृतियों से — अपनी जड़ों और स्मृतियों की ओर लौटती दृष्टि।

अथ श्री प्रयाग कथा — शहर, समाज और समय की पड़ताल।

चाकरी चतुरंग — प्रशासनिक व्यवस्था को भीतर से देखने वाली व्यंग्यात्मक दृष्टि।

कारी तू कभी ना हारी — पिता के संघर्ष, संस्कार और जीवन-मूल्यों की भावपूर्ण कथा।

कल फिर जब सुबह होगी — उत्तराखंड के लोकजीवन और संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से समझने का प्रयास।

इन पांचों कृतियों में अलग-अलग विषय हैं, लेकिन इनके बीच एक साझा सूत्र दिखाई देता है— **मनुष्य, समाज और उसकी संवेदनाएं।**

सुशासन की राह पर संवेदनशील दृष्टि

नैनीताल में जिलाधिकारी के रूप में श्री ललित मोहन रयाल की भूमिका का आकलन उनके कार्यकाल के आंकड़ों, प्रशासनिक निर्णयों और आने वाले समय में उनके कार्यों के आधार पर होता रहेगा। लेकिन उनके व्यक्तित्व का साहित्यिक पक्ष आज ही एक अलग पहचान प्रस्तुत करता है।

नैनीताल में जिलाधिकारी के रूप में श्री ललित मोहन रयाल की भूमिका का आकलन उनके कार्यकाल के आंकड़ों, प्रशासनिक निर्णयों और आने वाले समय में उनके कार्यों के आधार पर होता रहेगा। लेकिन उनके व्यक्तित्व का साहित्यिक पक्ष आज ही एक अलग पहचान प्रस्तुत करता है।

एक ओर प्रशासन की जिम्मेदारी, दूसरी ओर साहित्य की साधना।

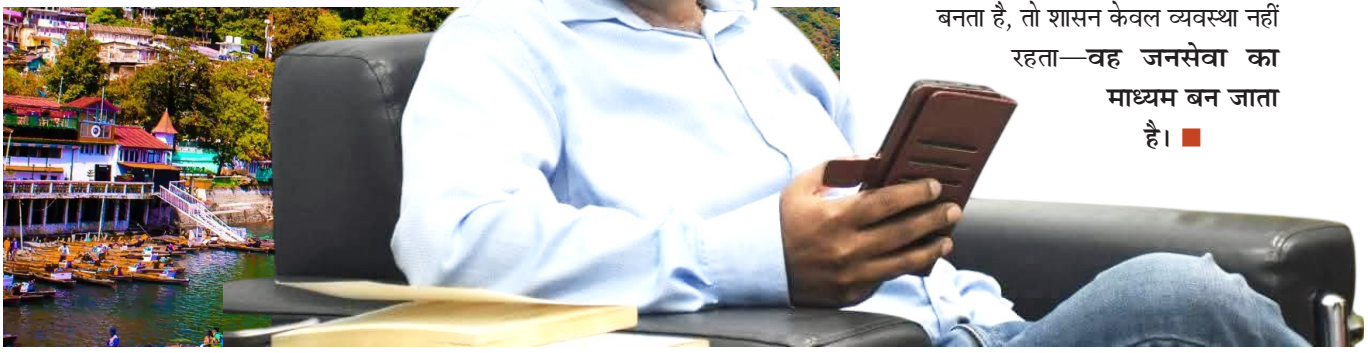
एक ओर सरकारी व्यवस्था की कठोर प्रक्रियाएं, दूसरी ओर लोकजीवन की कोमल संवेदनाएं।

एक ओर निर्णय लेने वाला अधिकारी, दूसरी ओर समाज को महसूस करने वाला लेखक।

शायद यही संगम उनके व्यक्तित्व को सबसे अलग ढंग से परिभाषित करता है—

"कलम समाज को समझती है और प्रशासन समाज के लिए काम करता है।"

और जब इन दोनों के बीच संवेदना का सेतु बनता है, तो शासन केवल व्यवस्था नहीं रहता—**वह जनसेवा का माध्यम बन जाता है।** ■



जब अपनी जरूरत से पहले दूसरों की चिंता बनी बदलाव की वजह

लवप्रीत की संवेदनशील सोच को मिला मुख्यमंत्री धामी का साथ, घर तक पहुंचा डिजिटल शिक्षा का साधन

लवप्रीत की संवेदनशील सोच को मिला डिजिटल शिक्षा का साथ

किसी बच्चे के हाथ में पहुंचा एक टैबलेट महज एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होता। कई बार वह उस बच्चे के लिए ज्ञान की नई खिड़की, सीखने का नया रास्ता और अपने सपनों तक पहुंचने का एक साधन बन जाता है। हरिद्वार की छात्रा लवप्रीत कौर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फर्क इतना था कि उसने अपनी जरूरत बताने से पहले उन विद्यार्थियों की चिंता की, जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी डिजिटल संसाधन नहीं हैं।



'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन' के दौरान लवप्रीत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी बात रखी। उसकी चिंता व्यक्तिगत सुविधा तक सीमित नहीं थी। उसने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता सामने रखी। एक विद्यार्थी का इस तरह दूसरे विद्यार्थियों के बारे में सोचना कार्यक्रम के बीच एक मानवीय क्षण बन गया।

लवप्रीत की इसी सोच ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। प्रस्तावित व्यवस्था में पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दिए जाने की बात कही गई। उद्देश्य स्पष्ट है—डिजिटल संसाधनों की कमी किसी विद्यार्थी की पढ़ाई और प्रतिभा के रास्ते में बाधा न बने।

लेकिन लवप्रीत के लिए इस पहल का एक व्यक्तिगत अध्याय भी जुड़ गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारी उसके घर पहुंचे और उसे टैब सौंपा। घर की चौखट पर पहुंचे इस छोटे से डिजिटल उपकरण ने उस दिन लवप्रीत के चेहरे पर बड़ी खुशी ला दी।

शायद उसे यह उम्मीद नहीं रही होगी कि कार्यक्रम में कही गई उसकी बात इतनी जल्दी उसके अपने जीवन का हिस्सा बन जाएगी। टैब हाथ में आने पर उसकी खुशी सहज थी और मुख्यमंत्री के प्रति उसके मुंह से निकला 'थैंक्यू' उस पूरे प्रसंग का सबसे आत्मीय हिस्सा बन गया।

यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डिजिटल शिक्षा के साथ एक सामाजिक संदेश भी छिपा है। तकनीक तभी सार्थक होती है, जब वह अवसरों की दूरी कम करे। ऑनलाइन अध्ययन, डिजिटल पाठ्य सामग्री और ज्ञान के व्यापक स्रोतों तक पहुंच आज शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों तक तकनीकी संसाधन पहुंचाना शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है।

लवप्रीत के हाथ में पहुंचा टैब उसके लिए पढ़ाई का साधन है, लेकिन उसकी कहानी उससे कहीं आगे जाती है। उसने यह याद दिलाया कि युवा पीढ़ी के भीतर अपने साथियों के लिए सोचने की भावना भी मौजूद है। अपनी जरूरत से पहले किसी और की जरूरत को महसूस करना संवेदनशील समाज की मजबूत बुनियाद है।

सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से टैबलेट उपलब्ध कराने की पहल इसी व्यापक डिजिटल शिक्षा की तस्वीर का हिस्सा है। इसका वास्तविक महत्व तब और बढ़ेगा, जब तकनीकी सुविधा के साथ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री, मार्गदर्शन और सीखने का उपयुक्त वातावरण भी लगातार मिलता रहे।

लवप्रीत की कहानी में इसलिए केवल एक टैब मिलने की खुशी नहीं है। इसमें एक विद्यार्थी की आवाज, शासन तक पहुंचा एक संवेदनशील सुझाव और उस सुझाव पर हुई त्वरित पहल—तीनों दिखाई देते हैं। यही संवाद किसी भी शिक्षा व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाता है।

कभी-कभी बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि एक विद्यार्थी की छोटी-सी बात से होती है। लवप्रीत ने अपनी बात में दूसरों की जरूरत को जगह दी और बदले में उसे अपने सपनों को आगे बढ़ाने का एक नया साधन मिला। उसके घर पहुंचा टैब इस बात का प्रतीक बन गया कि संवेदनशील सोच, संवाद और अवसर—मिलकर किसी विद्यार्थी की शिक्षा की राह को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। ■

बिहार की औद्योगिक उड़ान को नई रफ्तार



ग्लोबल बिजनेस समिट में दिखी निवेश, कौशल और रोजगार की नई तस्वीर

कभी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाने जाने वाला बिहार अब अपनी औद्योगिक संभावनाओं को नई पहचान देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेश के अनुकूल वातावरण, बेहतर औद्योगिक आधारभूत संरचना, नीतिगत सुधार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की पहल ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में नई उम्मीद जगाई है। इसी बदलती तस्वीर को राष्ट्रीय और वैश्विक उद्योग जगत के सामने मजबूती से रखने का अवसर **ICC Global Business Summit–Edition 2** में बिहार को मिला।

समिट के **टाइटल पार्टनर** के रूप में बिहार ने अपने औद्योगिक सामर्थ्य, निवेश की संभावनाओं और कारोबारी अवसरों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। आयोजित **बिहार स्टेट सेशन** में उद्योग मंत्री **सुश्री श्रेयसी सिंह** ने राज्य के बढ़ते औद्योगिक इकोसिस्टम और निवेश-अनुकूल वातावरण को रेखांकित किया। उनके साथ उद्योग विभाग के सचिव **श्री कुंदन कुमार,** रेजिडेंट कमिश्नर **श्री मनोज कुमार सिंह** तथा निदेशक MSME **श्री अमन समीर** भी उपस्थित रहे।

उद्योग जगत से सीधा संवाद, अवसरों पर मंथन

समिट का महत्वपूर्ण पक्ष रहा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित **Business-to-Government (B2G)** संवाद। इसमें निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने बिहार में निवेश की संभावनाओं, उद्योगों की आवश्यकताओं, कारोबारी सुगमता और सरकार के साथ सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

यह संवाद केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उद्योगों की वास्तविक जरूरतों को समझने और उनके अनुरूप नीतिगत एवं संस्थागत सहयोग विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया।

MSME क्षेत्र के लिए कौशल विकास पर जोर

बिहार के औद्योगिक विकास में MSME क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए **RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance)** के तहत सेक्टर-विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण के लिए **Sector Skill Council के साथ MoU** किया गया।

इस पहल का उद्देश्य उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। उद्योग की मांग और युवाओं के कौशल के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलने की संभावनाएं हैं। यह कदम बिहार के MSME सेक्टर को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

नीति, आधारभूत संरचना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का समन्वय

उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार प्रगतिशील नीतियों, बेहतर औद्योगिक आधारभूत संरचना और **Ease of Doing Business** पर निरंतर फोकस के साथ औद्योगिक विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उद्योग जगत के साथ संवाद को उन्होंने निवेश, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

वहीं उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार ने औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बेहतर आधारभूत संरचना, निवेश केंद्रित नीतियों और सरल प्रक्रियाओं पर जोर दिया। उन्होंने उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को MSME क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास के लिए अहम बताया।

बिहार पवेलियन में दिखी बदलते राज्य की तस्वीर

समिट में बिहार पवेलियन का उद्घाटन उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह ने किया। पवेलियन में राज्य की औद्योगिक क्षमता, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश अवसरों तथा निवेश के लिए तैयार हो रहे इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया गया। ■

औद्योगिक विकास की यह पहल बिहार को निवेश के नए मानचित्र पर स्थापित करने के साथ-साथ स्थानीय प्रतिभा, उद्यमिता और रोजगार को मजबूत आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जब हुनर को मिला अवसर, तो अर्चना ने लिखी आत्मनिर्भरता की कहानी

गृहिणी से सफल उद्यमी बनने का सफर—अमेठी की अर्चना त्रिपाठी ने ब्यूटी पार्लर को बनाया आत्मनिर्भरता का आधार

कभी-कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बस एक अवसर चाहिए—और उस अवसर को पहचानने का साहस। अमेठी की अर्चना त्रिपाठी की कहानी इसी विश्वास की जीवंत मिसाल है। घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने वाली अर्चना के मन में अपना काम शुरू करने का सपना था, लेकिन पूंजी की कमी उस सपने के आगे दीवार बनी हुई थी। फिर उन्हें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी मिली। बैंक से मिले सहयोग ने उस दीवार में रास्ता बनाया और अर्चना ने अपने हुनर को कारोबार का रूप दे दिया।

जनवरी 2025 में **2.12 लाख रुपये के ऋण** से शुरू हुआ 'अर्चना ब्यूटी पार्लर' आज उनकी नई पहचान बन चुका है। मुसाफिरखाना क्षेत्र की रहने वाली अर्चना अब अपने व्यवसाय से लगभग **30 से 40 हजार रुपये प्रतिमाह** की आय अर्जित कर रही हैं। छह सदस्यों वाले परिवार में उनकी कमाई आर्थिक संबल के साथ उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रही है।

बैंक के माध्यम से योजना की जानकारी मिलने के बाद अर्चना ने आवेदन किया। आर्थिक संसाधनों की चुनौती के बावजूद उन्होंने अपने सपने पर भरोसा किया। वित्तीय सहायता मिलने के बाद उन्होंने ब्यूटी पार्लर शुरू किया और धीरे-धीरे अपने व्यवसाय को स्थानीय स्तर पर पहचान दिलाई।

अर्चना की सफलता उस बदलाव की कहानी है, जहां सहायता की एक पहल आत्मनिर्भरता की एक नई शुरुआत बन जाती है।

कमाई से आगे बढ़कर आत्मविश्वास की कहानी

अर्चना की सफलता का सबसे बड़ा पहलू केवल उनकी मासिक आय नहीं, बल्कि वह आत्मविश्वास है जो उद्यमिता ने उन्हें दिया है। अब वह परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और अपने भविष्य को लेकर नए लक्ष्य तय कर रही हैं।

उनका अगला लक्ष्य अपने व्यवसाय का विस्तार करना है। वह मानती हैं कि यदि महिलाओं को सही अवसर, मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग मिले, तो वे अपने हुनर को सफल व्यवसाय में बदल सकती हैं। यही कारण है कि अर्चना की कहानी अब उनके परिवार की कहानी भर नहीं रही; वह आसपास की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है।

एक महिला की सफलता, कई सपनों की उम्मीद

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की सार्थकता अर्चना जैसी कहानियों में दिखाई देती है। जब आर्थिक सहायता किसी महिला को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देती है, तो उसका असर आय से कहीं आगे जाता है। परिवार मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में यह विश्वास पैदा होता है कि **स्वरोजगार के जरिए महिलाएं भी अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय कर सकती हैं।**

अर्चना की कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि 2.12 लाख रुपये की आर्थिक मदद ने सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर शुरू नहीं कराया—उसने एक महिला के भीतर छिपी उद्यमी पहचान को सामने आने का अवसर दिया।

आज अर्चना अपने व्यवसाय के साथ आगे बढ़ रही हैं और उनके सपने भी उनके साथ विस्तार पा रहे हैं। उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि **जब हुनर को अवसर, मेहनत को सहयोग और सपनों को सही दिशा मिलती है, तो एक गृहिणी भी अपने परिवार की आर्थिक ताकत और समाज की प्रेरणा बन सकती है।** ■







लाक्षागृह की लोककथा से लाख की कलाकारी तक

पांच पीढ़ियों से रंगों में रची राजस्थान की विरासत, इफ्तेखार अहमद के हाथों मिल रही नई पहचान



राजस्थान की पहचान केवल उसके किलों, महलों और लोकगीतों तक सीमित नहीं है। यहां की मिट्टी में सदियों से ऐसी हस्तशिल्प परंपराएं भी जीवित हैं, जिनमें इतिहास, संस्कृति और कारीगरों की पीढ़ियों की मेहनत एक साथ दिखाई देती है। **लाख की चूड़ियां और आभूषण** इसी समृद्ध विरासत का खूबसूरत हिस्सा हैं। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित दस दिवसीय 'तीजोत्सव-2026' में राजस्थान की यही पारंपरिक लाख कला लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी।

रंग-बिरंगी लाख की चूड़ियों और आभूषणों से सजा स्टॉल मेले में आने वाली महिलाओं और अन्य आगंतुकों को सहज ही अपनी ओर खींच रहा है। पारंपरिक तकनीक से हाथों से तैयार की गई इन चूड़ियों में रंगों का आकर्षक संयोजन, बारीक डिजाइन और राजस्थानी संस्कृति की विशिष्ट झलक दिखाई देती है।

पांच पीढ़ियों की विरासत, एक शिल्पकार का संकल्प

इस कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटे शिल्पकार **इफ्तेखार अहमद** की कहानी भी लाख की चूड़ियों जितनी ही रंगीन है। उनका परिवार पिछले **पांच पीढ़ियों से लाख शिल्प** से जुड़ा हुआ है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती तकनीक, अनुभव और हुनर के माध्यम से उनका परिवार लाख की चूड़ियों एवं विभिन्न आभूषणों का निर्माण करता आ रहा है।

इफ्तेखार अहमद के लिए यह केवल रोजी-रोटी का माध्यम नहीं, बल्कि **पुश्तैनी विरासत और सांस्कृतिक जिम्मेदारी** है। उनका प्रयास है कि बदलते दौर में भी लाख शिल्प की पहचान और उसकी पारंपरिक खूबसूरती बरकरार रहे।

इफ्तेखार अहमद के हाथों में सजी लाख की हर चूड़ी एक संदेश देती है— परंपरा तभी जीवित रहती है, जब उसे अगली पीढ़ी तक हुनर, सम्मान और नए अवसरों के साथ पहुंचाया जाए।

राजस्थान से दुनिया तक पहुंची लाख की चमक

इफ्तेखार अहमद बताते हैं कि उनकी कला को देश के साथ-साथ विदेशों में भी सराहना मिली है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपनी कला प्रदर्शित करने के अवसरों ने उन्हें यह विश्वास दिया कि पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प की वैश्विक बाजार में भी मजबूत संभावनाएं हैं।

बीकानेर हाउस का तीजोत्सव उनके लिए एक नया अनुभव रहा, जहां उन्हें सीधे ग्राहकों से संवाद करने और अपनी कला की विशेषताओं को समझाने का अवसर मिला। ऐसे आयोजन शिल्पकारों को **मंच, बाजार और ग्राहक—तीनों से जोड़ने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लाख में इतिहास, चूड़ियों में संस्कृति

लोक मान्यताओं में लाख का संबंध महाभारत काल के लाक्षागृह की कथा से भी जोड़ा जाता है। हालांकि लाख शिल्प की वास्तविक ऐतिहासिक यात्रा इससे कहीं व्यापक है, लेकिन यह लोकस्मृति इस कला को भारतीय सांस्कृतिक चेतना से जोड़ती है।

आज लाख की चूड़ियां केवल श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि **राजस्थान की जीवंत हस्तशिल्प पहचान** हैं। तीजोत्सव जैसे आयोजन इस विरासत को नई पीढ़ी, नए बाजार और नए ग्राहकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। ■

आइडिया की उड़ान, रोजगार की नई राह

आगरा के युवाओं ने 'यूपी राइज 2026' में दिखाई स्टार्टअप की ताकत





कहानी
छोटी-छोटी शुरुआतों से बड़ी संभावनाओं तक पहुंचने की है—और आगरा के युवाओं ने इस सफर की पहली तस्वीर दिखा दी है।

नौकरी की कतार से निकलकर नौकरी देने की राह पर बढ़ता युवा। समस्या में अवसर तलाशती नजर और आइडिया को हकीकत में बदलने का जुनून—आगरा में 'यूपी राइज 2026' के मंच पर युवा उद्यमिता की यही नई तस्वीर दिखाई दी।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर में आयोजित इस आयोजन में 1,000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। किसी ने इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस का मॉडल तैयार किया, तो किसी ने सोलर पैनल की सफाई, ई-रिक्शा की बैटरी, पर्यटन और मंदिरों के कचरे जैसी रोजमर्रा की चुनौतियों में नए कारोबार की संभावनाएं खोजीं।

कार्यक्रम में सामने आए 30 स्टार्टअप आइडियाज में से 11 को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें तकनीक, पर्यावरण, पर्यटन, हस्तशिल्प और स्थानीय जरूरतों से जुड़े ऐसे विचार शामिल रहे, जो बताते हैं कि कैंपस का युवा अब केवल **'नौकरी पाने'** के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि **'रोजगार बनाने'** की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है।

इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस **'Re-Oil'** ने प्रथम पुरस्कार हासिल कर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि जीती। **'Study App'** और **'Solar Sweep'** संयुक्त रूप से रनरअप रहे। यह आयोजन सिर्फ प्रतियोगिता नहीं था। यह युवाओं के आइडिया को सही दिशा, मार्गदर्शन और अवसर से जोड़ने की कोशिश भी था। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की युवा उद्यमिता, स्टार्टअप और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा विशेषज्ञ मेंटर्स ने प्रतिभागियों को अपने विचारों को व्यावहारिक बिजनेस मॉडल में ढालने के गुर बताए। ■



विजन से उपलब्धि तक
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में विकसित उत्तराखंड की दिशा

किसी राज्य के विकास की पहचान केवल भविष्य की योजनाओं से नहीं होती, बल्कि उस स्पष्ट विजन से होती है, जो योजनाओं को धरातल पर परिणामों में बदलता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की विकास यात्रा भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है— **स्पष्ट विजन, दृढ़ संकल्प और धरातल पर दिखाई देते परिणाम।**

खटीमा में आयोजित 'युवा समसामयिक संवाद' के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जिस विकास दृष्टि को सामने रखा, उसमें उत्तराखंड के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा दिखाई दी। युवाओं के लिए रोजगार, सीमांत क्षेत्रों का विकास, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन, पर्यटन का विस्तार, आधुनिक सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण—ये सभी मुख्यमंत्री के विकसित उत्तराखंड के विजन के महत्वपूर्ण आधार हैं।

युवा-केंद्रित विजन, रोजगार की ठोस उपलब्धियां

मुख्यमंत्री धामी का स्पष्ट विजन है कि उत्तराखंड के युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए अपने प्रदेश से बाहर जाने की मजबूरी न हो। इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी गई है।

संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक लगभग **34 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं।** यह उपलब्धि केवल रोजगार के आंकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को अवसर देने और उनकी क्षमता पर विश्वास करने के सरकार के विजन का परिणाम है।

सरकार की सोच रोजगार को केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित रखने की नहीं है। कौशल विकास, स्वरोजगार, पर्यटन और स्थानीय उद्यमों के माध्यम से युवाओं के लिए व्यापक अवसर तैयार करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि उत्तराखंड का युवा अपने ही प्रदेश में भविष्य की संभावनाएं देखे और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बने।

'विकल्प रहित संकल्प'—विजन से विकास तक

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व का मूल मंत्र **'विकल्प रहित संकल्प'** उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की विकास दृष्टि से जुड़ा है। उनका विजन है कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, युवा शक्ति, पर्यटन क्षमता, कृषि और मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।

इसी विजन के अनुरूप बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, हवाई सेवाओं, आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश और बेहतर जीवन स्तर की आधारशिला भी है।

सीमांत क्षेत्रों के विकास का विजन, 'प्रथम गांव' की नई सोच

मुख्यमंत्री धामी की विकास दृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में सीमांत क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है। उनका स्पष्ट विचार है कि सीमांत क्षेत्र देश का अंतिम छोर नहीं, बल्कि भारत के **'प्रथम गांव और प्रथम क्षेत्र'** हैं।

यह सोच केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का विजन है कि सीमांत क्षेत्रों से पलायन रुके और स्थानीय युवाओं को अपने गांव और आसपास ही रोजगार के अवसर मिलें। इस प्रकार सीमांत क्षेत्रों का विकास केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को सशक्त बनाने का प्रयास है।

पर्यटन का विजन, बढ़ती आर्थिक संभावनाएं

उत्तराखंड की प्राकृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मुख्यमंत्री धामी ने विकास और रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, हवाई सेवाओं और





होमस्टे जैसी सुविधाओं के विस्तार का सकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्र में दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में पर्यटकों की वार्षिक संख्या **7 से 8 करोड़ के पार** पहुंच चुकी है। चंपावत, मुनस्यारी, कौसानी, बेरीनाग, चौकोड़ी, पंचाचूली और आदि कैलाश जैसे क्षेत्रों में पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर्यटन के विस्तार की नई संभावनाओं को दर्शाती है।

यह उपलब्धि मुख्यमंत्री के उस विजन से जुड़ी है, जिसमें पर्यटन को केवल राज्य की पहचान नहीं, बल्कि **स्थानीय रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार का सशक्त माध्यम** बनाने की सोच शामिल है।

'विकल्प रहित संकल्प' के साथ मुख्यमंत्री धामी का लक्ष्य एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण है, जहां विकास अवसर बने, सुशासन विश्वास बने और युवा शक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनकर विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की यात्रा को नई गति दे।

सुशासन का विजन, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश

विकसित राज्य के निर्माण में सुशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री धामी ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था को अपने विकास विजन का प्रमुख आधार बनाया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ **'जीरो टॉलरेंस'** की नीति इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिकों को टोल-फ्री नंबर 1064 और अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था यह संदेश देती है कि शासन व्यवस्था में आम नागरिक की आवाज को महत्व दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि विकास तभी सार्थक है, जब शासन व्यवस्था पारदर्शी हो और जनता को बिना किसी बाधा के सरकारी सेवाओं का लाभ मिले। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को उत्तराखंड के सुशासन मॉडल से जोड़कर देखा जा सकता है।

प्रकृति के संरक्षण के साथ विकास का संतुलित मॉडल

उत्तराखंड की पहचान उसकी हिमालयी प्रकृति, नदियों, वनों और जैव विविधता से जुड़ी है। मुख्यमंत्री धामी का विजन विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलने का है।

सड़क, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान प्राथमिकता देने की बात मुख्यमंत्री ने युवा संवाद के दौरान दोहराई। यह सोच उत्तराखंड के लिए एक संतुलित विकास मॉडल की आवश्यकता को दर्शाती है, जिसमें आधुनिकता के साथ प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।

संवाद से सहभागिता तक—युवा शक्ति को नेतृत्व का विश्वास

18 विद्यालयों के लगभग **360 विद्यार्थियों** के साथ मुख्यमंत्री का सीधा संवाद उनके नेतृत्व की सहभागी सोच को दर्शाता है। युवा रोजगार, पर्यटन, पर्यावरण और भविष्य से जुड़े सवाल पूछें और राज्य का नेतृत्व उन्हें सीधे जवाब दे—यह एक मजबूत लोकतांत्रिक संस्कृति का संकेत है।

मुख्यमंत्री धामी का विजन युवाओं को केवल भविष्य का नागरिक मानने तक सीमित नहीं है। वह उन्हें आज के उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बनाने की सोच रखता है। यही कारण है कि युवा संवाद जैसे कार्यक्रम शासन और समाज के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बनते हैं।

विजन स्पष्ट, परिणाम दिखाई दे रहे हैं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की विकास यात्रा का संदेश स्पष्ट है— **विजन को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उसे उपलब्धियों और परिणामों में बदलना।**

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, सीमांत क्षेत्रों को 'प्रथम गांव' के रूप में विकसित करने की सोच, पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई गति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और पर्यावरण के साथ संतुलित विकास—ये सभी उस व्यापक विजन के अलग-अलग आयाम हैं। ■

सोन का पानी, उम्मीदों की नई धारा

25 साल बाद हुआ जल समझौता : अब खेतों, घरों और जीवन में बह सकती है विकास की नई उम्मीद

पानी का बंटवारा कभी केवल आंकड़ों का विषय नहीं होता। किसी किसान के लिए पानी का मतलब हरी फसल है, किसी मां के लिए घर तक पहुंचता पेयजल है, किसी गांव के लिए बेहतर जीवन है और किसी युवा के लिए रोजगार की नई संभावना। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर हुआ ऐतिहासिक समझौता इसलिए केवल दो राज्यों के बीच एमओयू नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ा एक नया अध्याय है।

करीब **25 वर्षों से लंबित विवाद** के समाधान के बाद बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2.00 मिलियन एकड़ फीट जल आवंटित करने पर सहमति बनी है। यह निर्णय विशेष रूप से दक्षिण बिहार और झारखंड के सूखा प्रभावित एवं पठारी क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।

किसान के खेत तक पहुंचेगी उम्मीद

पानी की कमी का सबसे बड़ा असर किसान के जीवन पर पड़ता है। समय पर सिंचाई नहीं मिलने पर उसकी मेहनत, बीज और उम्मीदें मौसम के भरोसे रह जाती हैं। सोन नदी के जल का बेहतर उपयोग होने से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की संभावना बढ़ेगी।

यदि खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचेगा तो किसान को फसल बचाने के लिए केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बेहतर सिंचाई से खेती की संभावनाएं बढ़ेंगी और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है।

घर-घर में जल, जीवन में राहत

जल समझौते का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं है। बेहतर जल उपलब्धता से पेयजल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

कई ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता मजबूत होती है, तो उनके समय और श्रम की बचत होगी। यह बचा हुआ समय बच्चों, परिवार और आजीविका के बेहतर अवसरों में लगाया जा सकेगा।

गांवों में विकास की नई संभावनाएं

पानी केवल जीवन की जरूरत नहीं, बल्कि विकास की बुनियाद भी है। बेहतर जल उपलब्धता से कृषि आधारित रोजगार, छोटे उद्योग और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। युवाओं के लिए अपने ही क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

जलाशय निर्माण और सोन-फल्गु नदी जोड़ो परियोजना पर आगे बढ़ने से दक्षिण बिहार के कई इलाकों में जल प्रबंधन की नई व्यवस्था विकसित होने की उम्मीद है।

आस्था और विकास का संगम

गयाजी और आसपास के क्षेत्रों के लिए यह पहल विशेष महत्व रखती है। फल्गु नदी में बेहतर जल उपलब्धता होने पर पितृपक्ष मेले में आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं को तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्यों में सुविधा मिल सकती है। ■

यह समझौता बताता है कि जब राज्य आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर साझा हितों के लिए साथ आते हैं, तो फैसलों का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच सकता है।

सोन नदी का यह जल केवल खेतों को नहीं सींचेगा, बल्कि किसान की मेहनत, परिवारों की उम्मीद, गांवों के विकास और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी नई ऊर्जा देने की क्षमता रखता है।

25 साल बाद निकला समाधान का रास्ता अब इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है कि सोन की धारा के साथ विकास की धारा भी बिहार और झारखंड के जीवन में और मजबूत होगी।



विकास की रफ्तार को मिला नया विजन, YEIDA में निवेश से नागरिक सुविधाओं तक मजबूत होती तस्वीर



निवेश, रोजगार, लॉजिस्टिक्स और नागरिक सुविधाओं को साथ लेकर आगे बढ़ता यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA क्षेत्र आज जिस तेजी से औद्योगिक और शहरी विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें हालिया बोर्ड फैसलों की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई देती है। 28 सितंबर 2026 को हुई 93वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों को केवल फाइलों में दर्ज प्रशासनिक फैसलों के रूप में देखने के बजाय उस बदलते क्षेत्र की तस्वीर के रूप में देखा जा सकता है, जहां उद्योग, रोजगार, आधुनिक लॉजिस्टिक्स और नागरिक सुविधाएं एक साथ आकार ले रही हैं।

प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति में भी उल्लेखनीय बदलाव दर्ज हुआ है। 14 सितंबर 2026 तक वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल प्राप्तियां 4,222.37 करोड़ रहीं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 182.35 प्रतिशत अधिक हैं। इसी क्रम में **YEIDA Corpus Fund Investment Regulation 2026-27** के माध्यम से एक दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था तैयार की गई है। इसके अंतर्गत वन टाइम लीज रेंट और अन्य गैर-आवर्ती आय को अलग Corpus Fund में रखकर निवेश किया जाएगा और उससे प्राप्त ब्याज का उपयोग सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क और ग्रीन बेल्ट जैसी नागरिक सुविधाओं के रखरखाव में किया जाएगा।

औद्योगिक विस्तार की दिशा में **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क,** नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 8,000 हेक्टेयर में प्रस्तावित **Industrial Node** तथा **International Trade City** जैसी योजनाएं क्षेत्र के भविष्य को नई आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश हैं। इन परियोजनाओं से निवेश, रोजगार, निर्यात और सप्लाई-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलने की संभावना है।



जमीन पर हो रही गतिविधियों के आंकड़े भी इस बदलाव को स्पष्ट करते हैं। 4,000 वर्गमीटर से अधिक आकार के 295 औद्योगिक भूखंडों में 181 की लीज डीड पूरी हो चुकी है, 152 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है और 69 भूखंडों पर निर्माण शुरू हो गया है। 13 इकाइयों में उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। सेक्टर-28 के मेडिकल डिवाइस पार्क, सेक्टर-29 के अपैरल, एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट पार्क तथा सेक्टर-33 के टॉय पार्क में भी औद्योगिक गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं।

इस औद्योगिक तस्वीर का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण और स्वच्छता है। **YEIDA Waste Management (Regulation & Control) Bye-Laws, 2026** का प्रस्ताव और विभिन्न प्रकार के कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए तैयार DPR इस बात की ओर संकेत करता है कि औद्योगिक विस्तार के साथ पर्यावरणीय प्रबंधन को भी महत्व दिया जा रहा है।

विकास की इस कहानी में किसान भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित पात्र किसानों को 7 प्रतिशत भूखंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अब तक 10,069 आरक्षण पत्र जारी किए जा चुके हैं और 4,978 भूखंडों का नियोजन किया जा चुका है। किसानों को लगभग 3,142 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिकर राशि भी वितरित की जा चुकी है।

93वीं बोर्ड बैठक के फैसलों की व्यापक तस्वीर यही बताती है कि YEIDA क्षेत्र में विकास अब केवल औद्योगिक भूखंड आवंटित करने तक सीमित नहीं है। निवेश को वास्तविक उत्पादन में बदलना, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना, नागरिक सुविधाओं के रखरखाव के लिए दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था बनाना, पर्यावरणीय प्रबंधन को व्यवस्थित करना और किसानों के हितों को साथ लेकर आगे बढ़ना—ये सभी पहलें क्षेत्र के अगले चरण की दिशा तय कर रही हैं। ■



जब आइडिया कागज से निकलकर जमीन पर उतरेंगे

हरियाणा में नवाचार की नई राह—युवाओं के विचारों को सीड फंडिंग, शोध को मिलेगा वास्तविक समस्याओं से जुड़ने का अवसर

किसी युवा के मन में आया एक छोटा-सा विचार कभी-कभी बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस विचार को प्रयोगशाला से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया में आजमाने का अवसर मिले। हरियाणा सरकार की प्रस्तावित **'नवाचार योजना'** इसी सोच को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा स्टेट इनोवेशन सोसाइटी की पहली बैठक में योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। योजना की खासियत केवल यह नहीं है कि युवाओं और शोधकर्ताओं को आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि इसकी दिशा **'लैब से फील्ड और फील्ड से नीति'** की ओर रखी गई है। यानी विश्वविद्यालयों में तैयार होने वाला शोध केवल शोध-पत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि खेत, शहर, उद्योग, प्रशासन और समाज की वास्तविक जरूरतों तक पहुंचे।

योजना के तहत यदि किसी विद्यार्थी या शोधकर्ता के पास ऐसी तकनीक, अवधारणा या समाधान है, जो प्रदेश की किसी वास्तविक चुनौती को दूर करने में उपयोगी हो सकता है, तो उसे प्रोटोटाइप के रूप में विकसित करने के लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग का अवसर मिलेगा। चयनित प्रस्तावों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए **एक लाख रुपये तक की प्रारंभिक सहायता** उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके बाद परियोजना को संबंधित विभाग के समन्वय से आगे बढ़ाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

शोध की दिशा बदलेगी तो परिणाम भी बदलेंगे

आज विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में प्रतिभा की कमी नहीं है। चुनौती अक्सर यह होती है कि शोध और समाज की तत्काल जरूरतों के बीच दूरी बनी रहती है। नवाचार योजना इसी दूरी को कम करने का प्रयास करती दिखाई देती है।

हरियाणा@2047, सतत विकास लक्ष्य, डिजिटल गवर्नेंस, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, टिकाऊ कृषि, शहरी प्रबंधन और सामाजिक-आर्थिक समावेशन जैसे विषयों को प्राथमिकता देना इस बात का संकेत है कि सरकार शोध को प्रदेश की दीर्घकालिक विकास आवश्यकताओं से जोड़ना चाहती है।

इस सोच का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि समस्या पहले पहचानी जाए और फिर उसके अनुरूप ज्ञान तथा तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इससे शोध की उपयोगिता को केवल अकादमिक उपलब्धि के बजाय उसके सामाजिक प्रभाव के आधार पर देखने की संभावना बढ़ती है।

भूमिगत जल पर पायलट प्रोजेक्ट—एक वास्तविक चुनौती की ओर नजर

बैठक में भूमिगत जल की गुणवत्ता को लेकर एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए गए। उद्देश्य ऐसी

तकनीक और प्रक्रियाओं की संभावनाओं का अध्ययन करना है, जिनसे अनुपयोगी अथवा गैर-पीने योग्य पानी को उपयोगी बनाने अथवा आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया के जरिए पीने योग्य बनाने के समाधान विकसित किए जा सकें।

यही वह बिंदु है जहां 'नवाचार' शब्द जमीन से जुड़ता है। जल जैसी समस्या किसी प्रयोगशाला की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध गांवों, किसानों, परिवारों और आने वाली पीढ़ियों से है। यदि किसी शोधकर्ता का प्रयोग वास्तविक क्षेत्र में लोगों के लिए उपयोगी समाधान बन पाता है, तो शोध का अर्थ भी व्यापक हो जाता है।

गूगल, आईआईटी दिल्ली और एनआईटी कुरुक्षेत्र से सहयोग

हरियाणा राज्य इनोवेशन मिशन ने गूगल इंडिया, आईआईटी दिल्ली और एनआईटी कुरुक्षेत्र सहित विशेषज्ञ संस्थानों के साथ एमओयू किए हैं। ऐसे संस्थानों से तकनीकी सहयोग, एआई के उपयोग, स्टार्टअप मेंटरिंग और लॉजिस्टिक सहायता मिलने से नए विचारों को प्रोटोटाइप से आगे ले जाने का रास्ता मजबूत हो सकता है।

इस व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है क्योंकि किसी नए विचार को बाजार अथवा प्रशासनिक उपयोग तक पहुंचाने के लिए केवल आइडिया पर्याप्त नहीं होता। उसे तकनीकी परीक्षण, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, संसाधन और सही संस्थागत सहयोग की जरूरत होती है।

युवा प्रतिभा के लिए संदेश—सोचिए, प्रयोग कीजिए और समाधान खोजिए

हरियाणा की यह पहल युवाओं के लिए एक अलग तरह का अवसर पैदा करती है। किसी समस्या को देखकर केवल शिकायत करने के बजाय उसके समाधान के बारे में सोचना, उस विचार को शोध में बदलना और फिर उसे प्रयोग के स्तर तक ले जाना—यह प्रक्रिया प्रदेश में नवाचार की संस्कृति को मजबूत कर सकती है।

अंततः किसी भी नवाचार की सफलता इस बात से तय होती है कि वह कितने लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है। यदि विश्वविद्यालय का शोध किसान की लागत घटाता है, तकनीक पानी बचाती है, डिजिटल समाधान प्रशासन को सरल बनाता है या कोई नया प्रयोग रोजगार के अवसर पैदा करता है, तो वही नवाचार समाज के लिए वास्तविक उपलब्धि बनता है।

हरियाणा की नवाचार योजना का व्यापक संदेश इसी दिशा में है— **आइडिया केवल सोच बनकर न रह जाए, उसे प्रयोग मिले; प्रयोग केवल प्रयोगशाला में न रुके, उसे जमीन मिले; और जमीन पर सफल समाधान नीति का हिस्सा बनकर समाज तक पहुंचे।** ■

निवेश की रफ्तार से रोजगार तक, खेत से बाजार तक

हरियाणा की तीन नई नीतियां उद्योग, एमएसएमई और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी में

हरियाणा की औद्योगिक कहानी अब केवल बड़े निवेश तक सीमित नहीं रहना चाहती। नई दिशा में उद्योग के साथ रोजगार, एमएसएमई के साथ निर्यात और कृषि उत्पादन के साथ वैल्यू एडिशन को जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने **मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026, हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 और हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2026** से जुड़े प्रोत्साहनों और वित्तीय प्रावधानों को आगे बढ़ाया है।

इन तीनों नीतियों का साझा फोकस स्पष्ट है— **निवेश आए, उद्योग बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले और किसानों की उपज को बेहतर बाजार मिले।**

बड़ा निवेश, बड़ा रोजगार लक्ष्य

मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026 के तहत पहले पांच वर्षों में **5,305.89 करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय प्रावधान** के साथ 18 प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। नीति में **5 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित करने और 10 लाख नए रोजगार सृजित** करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रोत्साहन वितरण की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का प्रस्ताव है। प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर प्रोत्साहन की पहली 50 प्रतिशत राशि सात कार्य दिवसों में वितरित करने और विस्तृत जांच के बाद शेष राशि 45 कार्य दिवसों में जारी करने की व्यवस्था बताई गई है। आवेदन की ऑनलाइन निगरानी और सिंगल विंडो सिस्टम से प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है।

एमएसएमई को स्थानीय बाजार से वैश्विक बाजार तक

हरियाणा की अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भूमिका को देखते हुए एमएसएमई नीति का महत्व अलग है। नीति में वित्त, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, निर्यात, सस्टेनेबिलिटी और स्किल्स जैसे छह क्षेत्रों में **60 पहलों** का प्रावधान किया गया है।

अगले पांच वर्षों में **55,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश, 5 लाख से अधिक रोजगार और निर्यात को दोगुना करने** का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों से लेकर अनुभवी निर्यातकों तक के लिए गुणवत्ता प्रमाणन, निर्यात ऋण, बीमा, फ्रेट सहायता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी जैसी सुविधाओं का प्रावधान इस नीति को छोटे उद्यमों के लिए बाजार विस्तार की दिशा से जोड़ता है। ■



जब तकनीक बनेगी तरक्की की ताकत, उत्तर प्रदेश लिखेगा नई आर्थिक कहानी

आईटी से सेमीकंडक्टर तक—निवेश, रोजगार और नवाचार के जरिए बदल रहा है प्रदेश के विकास का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां विकास की अगली कहानी सिर्फ बड़े उद्योगों और बुनियादी ढांचे से नहीं, बल्कि **तकनीक और नवाचार** से भी लिखी जाएगी। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप—ये वे क्षेत्र हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा दे सकते हैं।

सरकार के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के बीच तकनीक आधारित उद्योगों पर बढ़ता जोर इसी बदलाव की ओर संकेत करता है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा बैठक में भी चर्चा का केंद्र यही रहा कि इन उभरते क्षेत्रों में निवेश को किस तरह तेज किया जाए और उसका लाभ रोजगार, कौशल विकास तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंचे।

सबसे दिलचस्प बदलाव यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था अब केवल महानगरों की कहानी नहीं रह गई है। डेटा सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप तक, तकनीक से जुड़े नए अवसरों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही कुशल युवाओं की मांग भी बढ़ती है—यानी एक निवेश कई स्तरों पर आर्थिक गतिविधि को जन्म दे सकता है।

प्रदेश की आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियों में निवेश आकर्षित करने के साथ सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे भविष्य के क्षेत्रों को जगह दी गई है। इन सेक्टरों की खासियत यह है कि इनका असर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है। एक ओर उत्पादन और सेवाओं का विस्तार होता है, तो दूसरी ओर नई कंपनियों, तकनीकी पेशेवरों और उद्यमियों के लिए अवसरों का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है।

युवाओं के नजरिए से देखें तो यह बदलाव और महत्वपूर्ण हो जाता है। तकनीकी उद्योगों का विस्तार रोजगार के पारंपरिक विकल्पों के साथ-साथ डिजिटल सेवाओं, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, डेटा, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्रों में करियर के रास्ते खोल सकता है। इसके लिए जरूरी होगा कि उद्योग की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास भी समान गति से आगे बढ़े।

यही वजह है कि हालिया समीक्षा में केवल निवेश की संख्या पर नहीं, बल्कि परियोजनाओं को जमीन पर उतारने, प्रोत्साहनों के वितरण में तेजी और विभागीय समन्वय पर भी ध्यान दिया गया। किसी भी औद्योगिक नीति की असली सफलता कागज पर दर्ज प्रावधानों से आगे जाकर तब दिखाई देती है, जब निवेश वास्तविक परियोजनाओं, नौकरियों और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलता है।

उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक तस्वीर में तकनीक का यह अध्याय अभी निर्माणाधीन है। लेकिन दिशा स्पष्ट दिखाई देती है— **निवेश के साथ नवाचार, उद्योग के साथ कौशल और तकनीकी विकास के साथ रोजगार।** यदि ये कड़ियां मजबूती से जुड़ती हैं, तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना और कब हासिल होगा, यह कई आर्थिक कारकों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश अपने विकास मॉडल में तकनीक को एक महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है। और यही बदलाव आने वाले वर्षों में प्रदेश की आर्थिक पहचान को पारंपरिक औद्योगिक नक्शे से निकालकर **डिजिटल और टेक्नोलॉजी संचालित अर्थव्यवस्था** की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। ■

पी एफ सी
PFC

(एक नवरत्न कंपनी)

राष्ट्र की सशक्त संधारणीय संवृद्धि की ओर अग्रसर

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा ऋणदाता

62,000 मेगावाट – कुल संचित इंडिया ऊर्जा क्षमता संवर्धन



उत्पाद एवं सेवाएं



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(नवरत्न सार्वजनिक कंपनी)

www.pfcindia.com

राज्यस्तर अधिनियम के लिए निवेशोन्मुख

/pfcindia | /pfcindia | /pfcindia

JINDAL

PANTHER®

TMT REBARS & CEMENT

Desh ki Shaan,
Har Nirmaan ki Jaan



Anti-Corrosive | Tamper Proof Bag | High Compressive Strength | Eco-friendly and Sustainable

Toll free number: 1800 208 2008